12.00 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77—Contd.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING—contd.

MR. SPEAKER: We now take up further discussion and voting on Demand for Grants for the Ministry of Information and Broadcasting. Time allotted is six hours. Time taken is fifty five minutes. Balance of the time is five hours and five minutes.

Dr. Rudra Pratap Singh

डा० रुद्रप्रताप सिंह (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय,

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, हमने आप को लिख कर भेजा था कि पटना मे पानी का बहुत भयंकर संकट है, लोगों को पानी नही मिल रहा है. . .

अध्यक्ष महोदय : डा० रुद्र प्रतापसिंह

डा० रुद्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानो की मांगों पर बोलने का अवसर दिया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हू । मान्यवर, यदि हम निष्पक्ष रूप से विचार करें तो आलोच्य वर्ष मे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा और सूचना मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया गया है उस की जितनी सराहना की जाय वह कम है । श्रीमन् मंत्रालय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश विरोधी दल के नेतागण तथा सदस्यगण जब मंत्रालय की अनुदान पर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए खड़े होते हैं तब वह सरकार की नीतियो की आलोचना करने लगते हैं और उनका ध्यान इस बात पर नही रहता कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का उत्तरदायित्व सरकार की नीतियों ,सरकार की योजनाओं और सरकार के कार्यक्रमो को जनता तक पहुंचाने तक का ही है ।

श्रीमन् आलोच्य वर्ष मे मंत्रालय अपने दायित्व का निर्वहन कर सका है अथवा नही, यह विचारणीय बात है । उसने अपने दायित्व का पालन किया है अथवा नही इसके सम्बन्ध मे विचार करते समय यह स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान इस ओर जाय कि हमारी सरकार की नीतिया क्या है, योजनाएं क्या है, उसके कार्यक्रम क्या है । श्रीमन्, हमारी सरकार की देश के अन्तर्गत जो नीतिया हैं जैसा कि माननीय सदन को ज्ञात है, वह नीतियां हैं लोकतन्त्र की, धर्मनिरपेक्षता की और समाजवाद की । विदेशो के साथ हमारी सरकार की नीति है मंत्री की, सद्भावना की और सहयोग की । हमे प्रसन्नता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सरकार की जो नीतिया हैं देश के अन्तर्गत और विदेशों के साथ मे, उन नीतियो को उन योजनाओ को और कार्यक्रमो को जनता तक पहुचाने मे सफलतापूर्वक कार्य किया है ।

श्रीमन् जैसा कि माननीय सदन को ज्ञात है कि लोक सभा के 1971 के निर्वाचन के पश्चात् जिस तरह से विश्व की सर्वश्रेष्ठ नेता हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व मे एक नवीन भारत का उदय हो रहा था, उसके पश्चात् 1972 मे जो देश में और 1974 मे जो साधारण निर्वाचन हुए उससे जनता ने प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व मे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नीतियो मे अपनी आस्था और अपना विश्वास व्यक्त किया उससे देश के अन्तर्गत और विदेशो मे जहां

[डा० रुद्र प्रताप सिंह]

भी प्रतिक्रियावादी शक्तियां थीं, दक्षिणपंथी शक्तियां थीं, उग्रवादी शक्तियां थीं, अवसरवादी, यथास्थितिवादी शक्तियां थीं, सभी शक्तियों को बेचैनी हुई, और उन्होंने एक महान् गठबन्धन किया देश के अन्दर और बाहर भी। और इस महान गठबन्धन के फलस्वरूप उन्होंने देश के अन्दर एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जिस से देश की अखंडता को, प्रभुसत्ता को, देश के अन्तर्गत लोकतन्त्र को, देश की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हुआ। इतना ही नहीं हुआ, उन शक्तियों ने ऐसे भी कार्य किये कि जिस से देश के अन्दर साम्प्रदायिक सद्भावना भी समाप्त हो। साथ ही साथ उन्होने इस बात का भी प्रयास किया कि विदेशों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वह भी नष्ट हों। और इस प्रकार का जो कुचक्र उन्होने रचा, षडयन्त्र रचा, उस के कारण से देश की प्रधान मंत्री जी को देश में आपात्कालीन स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। देश मे आपात्कालीन स्थिति की घोषणा के बाद किन कारणो से आपात्कालीन स्थिति लागू की गई इस को हमारे सूचना मंत्रालय ने बहुत अच्छे ढंग से जनता तक पहुंचाया। हम उस बात के लिये अपने मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त आपात्कालीन स्थिति की घोषणा केवल इसलिये नहीं की गई थी कि हम केवल देश के अन्दर जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां देश का वातावरण खराब करना चाहती थीं उन पर अंकुश करना चाहते थे। हमारी सरकार यह भी चाहती थी कि देश के अन्दर जो हमारी योजनायें और कार्यक्रम हैं उनका उचित ढंग से कार्यान्वयन हो सके। इसके लिये प्रधान मंत्री जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। हमारे सूचना मंत्रालय ने अपने विभिन्न एककों के द्वारा जनता तक 20 सूत्री कार्यक्रम को पहुंचाने का जो कार्य किया है उसकी हमें सराहना करनी चाहिये।

श्रीमन्, देश के समाचार-पत्रों ने जिस प्रकार से इधर कार्य किया उस से माननीय सदन अवगत है। इधर समाचार-पत्रों ने देश के अन्दर एक ऐसी अस्थिरता का, अराजकता का और निराशा का वातावरण पैदा करना आरम्भ कर दिया था कि जैसे सरकार की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं उन का जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। माननीय सदन इस बात से सहमत होगा कि जब देश प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व मे विश्व के समस्त देशों की श्रेणी में बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा हो, वैसी परिस्थिति में अगर देश के समाचार-पत्र इस प्रकार के समाचार प्रकाशित करें जिस में कि देश के अन्दर देश की प्रभुसत्ता को, देश की अखंडता को, लोकतन्त्र को और देश के अन्दर जो साम्प्रदायिक सद्भावना है, उस को खतरा पैदा हो तो निश्चित रूप से उनके ऊपर सेंसर की नीति का अपनाया जाना बहुत ही उचित और समयानुकूल था, और मैं इस बात के लिये मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। देश के अन्दर और विदेशों के जो ऐसे संवाददाता थे जिन्होने समाचारों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की चेष्टा की जिस से देश की प्रभुसत्ता को, भावात्मक एकता को खतरा पैदा हो सकता था, ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्यवाही की गई।

इस के साथ ही मंत्री जी ने पिछले सत्र में जो एक आक्षेपनीय प्रकाशन निवारण अधिनियम संसद द्वारा पास कराया था, इस के लिये भी उन्हें बधाई देनी चाहिये।

श्रीमन्, फिल्में एक बहुत सशक्त माध्यम हैं हमारे जन-जीवन में फिल्मों में। नग्नता, अश्लीलता और हिंसा के सम्बन्ध में इस सदन में बारबार चिन्ता व्यक्त की गई। मैं इस बात के लिये भी मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आलोच्य वर्ष के अन्दर जो फिल्में बनी हैं वह कुछ नई किस्म की फिल्में बनी हैं, इस बात को स्वीकार करना

होगा। एक तरह से नई दिशा मिली है, आशा की एक नई किरण दिखाई पड़ी है। हमारे फिल्मों के निर्माता मंत्री जी के नेतृत्व में देश के अन्दर नये कथानकों की खोज मे लगे हुए हैं।

हमे आशा है कि अगले वर्ष और कुछ अच्छी फिल्मे आ सकेंगी इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय फिल्म समारोह, हमारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार योजना के द्वारा जिन अच्छी फिल्मो को पुरस्कृत करने का प्रयास किया गया है, उससे भी निर्माताओ को अच्छी फिल्मे बनाने की प्रेरणा मिल रही है।

श्रीमन् मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि यदि हम अच्छी फिल्मो का निर्माण करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत सम्पन्न फिल्म वित्त निगम की आवश्यकता है। इस समय जो हमारा फिल्म वित्त निगम है, उसे सुदृढ किया जाय, उसे वित्तीय साधन दिये जाये। अगर हम देश मे अच्छी फिल्मो का निर्माण करना चाहते है तो इसके लिए धन का प्रावधान किया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि देश मे अधिक सिनेमा घर बनाये जाये। इस सम्बन्ध मे एक ऐसी नीति बनाने की आवश्कता है जिससे देश के अन्दर अधिक से अधिक सिनेमा घर बन सकें।

मैं मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हू कि उन्होने फिल्म पत्रिकाओ मे जो अनर्गल चित्र और समाचार छपते थे, जो कि बहुत अनुचित होते थे, उनके सम्बन्ध मे फिल्म सेंसर बोर्ड को इस बात का निर्देश दिया है कि उनकी छानबीन की जाय।

दूर दर्शन के द्वारा हमारी नीतियों को, योजनाओं को, कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाया जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि आलोच्य वर्ष मे इस कार्य को अधिक से अधिक सुन्दर ढग से किया जा रहा है। इस बात की आवश्यकता है कि देश की, प्रदेश की और केन्द्र शासित प्रदेश की राजधानियों मे दूर दर्शन की सेवाएं उपलब्ध हों। इसके लिए धन के प्रावधान की नितान्त आवश्यकता है। इसके साथ साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि सस्ते टेलीविजन सेट बनाये जाये जिससे जनता को वे सस्ते दामो पर सुलभ हो सके। पहली अगस्त, 1975 से 31 जुलाई, 1976 तक उपग्रह दूर दर्शन को जो योजना चलाई गई हैं, उससे कई प्रदेशो को जनता को लाभ पहुंचा है। मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि इस योजना को और अधिक समय के लिए बढा दिया जाय जब तक कि हम उन क्षेत्रों को दूर दर्शन की सुविधा प्रदान नही करते।

श्रीमन् आकाशवाणी के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है आपात्कालीन स्थिति लागू होने के पश्चात उसने बहुत ही सफलतापूर्वक सरकार की नीतियों को, योजनाओं को, कार्यक्रमो को जनता तक पहुचाने का कार्य किया है। हमारे देश के कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनको आकाशवाणी को सुविधा प्राप्त नही है। उन्हे भी यह सुविधा प्रदान की जाये। उत्तर पूर्वी भारत के जो हमारे केन्द्र शासित क्षेत्र है, उन्हें हाई पावर रेडियो स्टेशन दिये जाये जिससे उन्हें विदेशो के समाचारो के अतिरिक्त अपने देश के समाचार मिलने का अवसर प्राप्त हो।

श्रीमन् मंत्रालय के विभिन्न एकको द्वारा, विशष कर विज्ञापन प्रचार निदेशालय द्वारा जिस प्रकार से आपातकालीन स्थिति की घोषणा के पश्चात् बीस सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में साहित्य वितरित किया गया,

[डा० रुद्र प्रताप सिंह]

वह प्रशंसा को पात्र है। इसके अतिरिक्त और भी जो एक है उन्होंने भी अपने अपने स्थान पर अपने अपने उत्तरदायित्व का बहुत अच्छे ढंग से पालन किया है ।

श्रीमन्, नवीन भारत के निर्माण की जो रोड़ को हुई है हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम, उसको भी मंत्रालय ने जनता तक बहुत अच्छे ढंग से पहुंचाया है । उसके लिए मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं । श्रीमन् मैं इस बात का भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे युवा हृदय सम्राट श्री संजय गांधी के द्वारा जो चार सूत्री कार्यक्रम रखा गया है, जो जनता को बराबर प्रेरणा दे रहे हैं, जनता का मार्गदर्शन कर रहे है, हमें दुख है कि आकाशवाणी और टेलीविजन के द्वारा विरोधी दलों की टीका टिप्पणी के भय से उन्हें वह स्थान नहीं दिया जा रहा है जो कि उनको मिलना चाहिए ।

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA (KHAMMAN): Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of order. As per the rules of the House, no Member can bring in the name of a person who is not persent in the House What is your ruling on this?

MR. SPEAKER: There is no point of order. The hon. member may continue his speech.

डा० रुद्र प्रताप सिंह : श्रीमन् मैं कह रहा था कि जब हमारी सरकार की नीति के अन्तर्गत कोई देश का नौजवान देश की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करता है तो उसको आकाशवाणी के द्वारा, दूर दर्शन के द्वारा जो भी स्थान दिया जाना चाहिए, वह दिया जाय । हमारे जो युवा नेता हैं उन्हें वह स्थान नहीं दिया जा रहा है । उन्हें कम स्थान दिया जा रहा है । उन्हें अधिक स्थान दिया जाना चाहिए ।

श्रीमन् मैं बहुत अधिक समय आपका नहीं लेना चाहता । मैं केवल एक बात कह कर समाप्त करूंगा । अन्त में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में, माननीय विरोधी दल के सदस्यगण, विशेष रूप से मेरे पूर्व वक्ता श्री सुरेन्द्र मोहन्ती ने जो अपने विचार प्रकट किए, और मेरे पश्चात् जो विरोधी दल के वक्ता अपना भाषण करेंगे, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि :

मुझे क्या बताएगा दौरे जमाना
मुझे मेरी मंजिल नजर आ रही है ।

इन शब्दों के साथ मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपने सुयोग्य मंत्री जी की सराहना करता हूं और साथ ही साथ मंत्रालय की अनुदान की मांगों का हृदय से समर्थन करता हूं ।

माननीय सदस्य अगर जानना चाहें तो मैं उनकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं । जब वह अपना भाषण करें तो इस बात का ध्यान रखें कि यह आवश्यक नहीं कि हम जीवन भर माननीय सदस्य के सदन रहें मगर जो कुछ हम यहां पर बोलते हैं वह सदैव इस माननीय सदन की स्मृति में रहेगा । इसलिए बोलते समय इस बात का ध्यान अवश्य ही रखें कि हम जो कुछ बोल रहे हैं, वह इस सदन की सामग्री होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan): Mr. Speaker, Sir, Shri Rudra Pratap Singh just now said something about the speakers who are to follow him. I do not know why he should worry about it because nothing we say will go out, nothing will be published. We know what happened to the speech of Mr. Surendra Mohanty delivered yesterday. In today's

papers there is no mention of it. Only in one or two papers it has been said that he also spoke. I do not grudge Mr. Patil getting good publicity for eulogizing the role of the Information and Broadcasting Ministry, but at least think of the Opposition parties. They have some role to play to the country and to the people. Therefore, my hon. friend need not have any apprehension about the role of the Opposition I say that the Opposition—at least my party—has been playing a very constructive role. There is not a single incident which could be cited against us.

So far as the present discussion on the grants of this Ministry is concerned, I say, Sir, that the functioning of this Ministry during the year under review provides—according to me—the most inglorious chapter of the functioning of the Government since Independence and it has been proved that this Government only pays lip sympathy to the Constitution and the parliamentary system of Government and parliamentary democracy and the rights of the people Mr. Shukla—we have personal regards for him—will have the unenviable distinction of master-minding, in the company of some more eminent and some less eminent persons, the annihilation of and giving an indecent burial to, some of the basic concepts of free people in this country. What we call the freedom of thought, the freedom of speech and the freedom of expression have become his victims. The record of this Ministry for the year under review is the record of partisan propoganda and censorship, of false calumny against the political opponents of the ruling party and of sickening eulogies of some of their leaders including those unelected and officially glorified, of suppressing truth and encouraging make-believes.

This Ministry know as the I&B Ministry has according to me, turned out to be the Ministry of Inexactitude and Brow-beating and it functions, as we can see, only as the publicity wing of the ruling party in this country through the simple means of censorship which is applied indiscriminately, and comprehensively also, against all except the ruling party and its members. This Ministry has, by and large, achieved its present purpose of doing away with the freedom of the press in this country.

With your permission, I will quote a very well-known author on political science and constitutional government. I am quoting from Prof. Friendrich, an American author who has written a book *Constitutional Government and Democracy*, where he has said:

> "Actually, the emergence of constitutional government and in particular, the crystalisation of the systems of popular representation are inextricably interwoven with the growth of the modern press, Without it, constitutional Government is unimaginable".

We have felt, and we believe, that freedom of the press is the cornerstone of democracy and a free press is a symbol of democratic virtue.

With your permission, I will quote from some of the observations of some very eminent judges of this country. Chief Justice Patanjali Sastri said in 1952:

> "Freedom of speech and of the press lay at the foundation of all democratic organisations, for without free political discussion, no public education, so essential for the proper functioning of the processes of popular government is possible".

He said this in the well-known Express Newspapers case. Then Justice Bhagawati (a former Judge) said in the Express Newspapers case speaking for the Supreme Court:

> "Freedom of speech and expression includes freedom of propagation of ideas and the liberty of the press is an essential pa[illegible]

[Shri Somnath Chatterjee]

right to freedom of speech and expression".

Our present Chief Justice, who was given this post after superseding a number of Judges, said this....

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA (Aurangabad): Before the superssion of after?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Before for your information. He said this:

"It is indisputable that by freedom of press is meant the right of all citizens to speak, publish and express their views. The freedom of the press embodies the right of the people to write. The freedom of the press is not antithetical to the right of the people to speak and express.

"This court has established freedom of the press to speak and express. That freedom cannot be abriged and taken away by any manner except as provided in art. 19 (2) of the Constitution".

Some of the restraints that have now been imposed would have been *ultra vires* the Constitution but for the suspension of all fundamental rights in this country.

Chief Justice Ray went on to say:

"It is appropriate to refer to what William Blackstone said in his Commentaries"—then quotes Blackstone:

"Every free man has an undoubted right to lay what sentiments he pleases before the public; to forbid this is to destroy the freedom of the press; but if he publishes what is improper, mischevious or illegal, he must take the consequences of his own temerity. The faith of a citizen is that political wisdom and virtue will sustain themselves in the free market of ideas so long as the channels of communication are left open. The faith in the popular government rests in the old dictum 'let the people have the truth and the freedom to discuss it and all will go well'. The liberty of the press remains an 'ark of the Covenant' in every democracy".

Shri Gujral had said that freedom of the press was a commitment of this Government. Now they have repudiated it.

With your permission, I will now quote not a learned judge but a great, distinguished stateman of this country:

"To my mind, the freedom of the press is not just a slogan from the larger point of view but it is an essential attribute of the democratic process. I have no doubt that even if the Government dislikes the liberties taken by the press and considers them dangerous, it is wrong to interfere with the freedom of the press. By imposing restriction, you do not change anything; you merely suppress public manifestation of certain things thereby causing the idea underlying that to spread further. There-I would rather have a completely free Press with all the dangers involved in the wrong use of the freedom than suppressed or regulated press."

Thus said Jawaharlal Nehru. I found yesterday that he was being quoted by our Labour Minister very frequently. They quote Pandit Nehru when it suits them. When we try to get some inspiration from Nehru's sayings or writings, then only it becomes out of context.

I know the Minister will give the usual worn out reply that the newspapers were supposedly abusing the licence. It is easy to give the dog a bad name and hang it. But I am challenging this government: instead of indulging in vague accusations and generalisations,

bring out the materials before the people and take people into confidence and tell them what they have done to merit this all-comprehensive censorship regulation which has completely throttled the voice of the people and voice of the Press. The Prime Minister has said yesterday, it has appeared in today's Statesman. "For years government had been tolerant and put up with the criticsm of the newspapers but then they seemed to turn against the country itself at a moment when we have been facing economic difficulties; what they set about doing would have weakened the whole structure ." Now the justification offered is economic difficulty'. From the events of June 1975 one understands what she means by turning 'against the country' because the country, according to the ruling party, is their leader. I should like to know from the hon. Minister how economic difficulties have been overcome by Press censorship. How are you solving the economic problems by throttling the voice of the people, and of the Press? I cannot imagine what is the *modus operandi* they seek to follow for the purpose of goading the country to economic progress? The reason is this. They would not have suppressed all kinds of publications, had they not been afraid of the people. They have suppressed the news of the arrest of the leaders—is it for the purpose of economic development? They have suppressed the proceedings of courts. Is that also for economic development of the country? The speeches of the Members of Parliament have been suppressed. Is it for economic development of the country? News of everything said or done by anybody else except their own hue is supposed to be prejudicial to the interests of the country and they have been suppressed. Is it because of the economic difficulties in the country, as the Prime Minister said yesterday?

Look at the guidelines. We have been told that censorship has been virtually withdrawn but guidelines have been imposed. May I need one of them? I have no time to read the whole of it; most of the hon. Members know them:

> "Quotations, if torn out of context and intended to mislead or convey a distorted or wrong impression, should not be published."

What I quoted today from the sayings of Jawaharlal Nehru, is it out of context? Will it be published in tomorrow's papers that Somnath Chatterjee quoted this in the House?

Another guideline says:

> "For the coverage of the news, comments or reports relating to the proceedings of Legislatures, Parliament and Court of law, the following guidelines should be kept in view· (a) The statements of Ministers may be published either in full or in a condensed form but its contents should not infringe censorship. (b) The speeches of Members of Legislatures/Parliament participating in a debate will not be publihed in any manner or form but their names and party affiliation may be mentioned (c) The results of voting on a Bill, Motion, Resolution etc may be factually reported In the event of voting the number of votes cast for and against may be mentioned ..

Please note that there should be no indication in the published material that it has been censored Printing of captions as "passed by Censors" or "passed for publication" is not permitted."

Those administrative directives were issued in July 1975. Now in January 1976 during the last session of the House, this guideline was issued:

> "Not withstanding anything contained in letter dated August 19, 1975, addressed to all accredited correspondents representing Indian news organisations and ...."

It says that all news, comments (including editorial comments), rumouror other reports relating to the

[Shri Somnath Chatterjee]

proceedings of the 15th Session of Fifth Lok Sabha, 1976 and 84th Session of the Rajya Sabha falling within the provisions of the said Statutory Order 276 (E) shall not be published scrutiny and shall not be published without permission in writing. This is *from* the *Chief* Censor of the Government of India. Therefore, it is very clear that this Government does not want anything for public consumption. Their own views should be known to the public and nct the views of others. These are the actions of a Government in panic. They are panicky because they know that their actions will not be supported by the people, if they are allowed free exercise of their rights and free voice. This Government has been returned to power with a minority vote of the total electorate, but they want to perpetuate their position by using all sorts of draconian powers and repressive measures. This Government seems to believe that they only know what is good for the people of this country. I was reading a book this moring It is one of the attributes of a high-handed Government that according to them the people are only entitled to know what they want the people to know irrespective of the considerations whether that would be good for the country or not The Government things that it is the only arbitor of the rights of the people of this country and the people themselves will have no voice.

Shri Seervai, a well-known jurist, who is not a memebr of any opposition party, nor is anti-government, has said in his well-known book 'Constitutional Laws of India'—

"It has been rightly observed that to say that a thing is constitutional is not to say that it is desirable." Therefore to say that restraints on the freedom of speech and expression are permissible under our Constitution is not to say that any particular restraint is desirable or ought to be imposed. The freedom of thought and expression and the freedom of press are not only valuable freedoms in themselves but are basic to a democratic form of Government which proceeds on the theory that problems of Government can be solved by the free exchange of thought and by public discussion. A plea for freedom of thought, speech and expression is not necessary, nor is it necessary to refer to classic pleas for the liberty of thought to show that restraint on the freedom of thought 'hinders and retards the importation of our richest Merchandise, Truth'.

The International Commission of Jurists in its Jounral has said: "It needs to emphasise that a free press which is neither directed by the Executive nor subzjected to censorship, is a vital element in a free State: in particular, a free, regularly published, political press is essential in a modern democracy. The citizen called upon to make political decisions, must be comprehensively informed, know the opinion of others, and be able to weigh them up against each other. The press keeps this dialogue alive, it provides the information, adopts its own point of view and that works as a directive giving force in the public debate It stands as a permanent means of communication and control between the people and their elected representatives in Parliament and Government."

Sir, why I am quoting all this? I am trying to say that the Judges of the Supreme Court of India, eminent Jurists, eminent public figures, great statesman like Pandit Jawaharlal Nehru, the International Commission of Jurists are all of the opinion that in a Constitutional system of Government you cannot have free people if you have denied them freedom of expression and freedom of press. Now, all these things have been repudiated by the Government and the real reason for enforcing Press Censorship followed by the abolition of the Press Council and the enactment of Parliamentary proceedings (Propagation of Publication) Repeal Bill and the Prevention of Publication of

Objectionable Matter Bill is that this Government and the Ruling party aro afraid of free people in this country. They are scared of the freedom of the people and their freedom to enjoy personal liberty.

This Government does not want scrutiny of their action either by the people or by the press or by the court because according to them, they are infallible. I believe only those want to hide facts from the people who have ugly facts to hide. Otherwise, in matters of public interests, all governmental action should be public Why do you want to hide facts from the people? They have stifled all vehicles of exchange of thought, all vehicles of expression of opinion and views and all channels of communication. If the Ruling party believes that the people are with them, why should they be afraid of the people? If they really believe that the opposition parties do not have any support amongst the people, why should they give importance to the opposition parties? Why are thev worried about the activities of the opposition parties amongst the people of this country? I submit that the Government, instead of having a dialogue with the people, has obliterated all forms of freedom—freedom of speech, freedom to organise and freedom of dissent.

If the big newspapers controlled by the monopolists have been misusing their freedom, I would like to know why the other publications are also being brought under control. Even liberary journals and small newspapers are not outside the net of censorship. Small newspapers who do not toe the line of the Government have not been spared. Literary journals have not been spared from the law of censorship. Even stage plays and dramatic performances are not permitted without clearance from the censorship authorities The country has today become a conglomeration of muted and muzzled people who cannot say anything except to drumbeat the so called achievements of the Ruling party. We ar seeing today the sickening example of officially sponsored, officially publicised and officially patronised publications and demonstrations. Today the great media of the press is being utilised as the biggest *modus operandi* for sponsoring not only particular view points but also sponsoring particular leaders.

I would like to know how the monopoly press in this country came to acquire such commanding heights except without the support of the Government and the Ruling party. We have been hearing tall talks about diffusion of ownership of the press and the delinking of the press from the big business houses But we find so long we have been taken for a ride. Mr Gujral has been repeatedly assuring the House in this regard. But there is not even a mention of it—subject to correction—in the annual report of this Ministry for this year under review I want to know what has happened to the diffusion and delinking It seems they are no longer interested in diffusion and delinking because the Ruling party had got itself linked up with the monopoly press itself. The only fusion we have found, instead of diffusion, is that of Shri Ramnath Goenka and Shri K. K. Birla in the *Indian Express*! Therefore, I would like the Minister to inform the House—his speech at least is bound to be published though not ours—what has happened to these policies of diffusion and delinking.

So far as the small newspapers and opposition party papers are concerned, although according to the Government they have removed pre-censorship, the guidelines they have laid down recently make it impossible for any effective or *bona fide* criticism being made of any governmental action.

But in the case of newspapers and journals published by our party, the Centre of Indian Trade Unions, All India Kisan Sabha etc., exception has been made and all of them are subject to pre-censorship. The Censor prevents publication in our newspapers

[Shri Somnath Chatterjee]

of even news items and comments which have been published in other newspapers. What is published, after pre-censorship, in one edition of "Deshabhimani" from Calicut or Ernakulam, is prohibited from publication by the Censor of the other edition. Items allowed to be published by the Censor in "People's Democracy", the English organ of our Central Committee is disallowed in other newspapers and journals of our party by the same or other Censors. Exception has been taken to the publication of even Gazette notifications of the Governments of West Bengal and Kerala in our newspapers! Even news items received through the teleprinter from the "Samachar" News Agency, which are sent out after censorsnip have to be submitted to the Censor, who prevents publications of many items. Even publication of the news of arrested persons is prevented.

Slanders and absolutely false statements about our party by the ruling party and their allies are freely published; but publication of any reply to those slanders and accusations are never allowed All these show that the Press is now completely at the mercy of the Government and the Censor authorities.

MR. SPEAKER: I think you should conclude now.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Kindly give me 3 or 4 minutes more please. Now, as far as getting the clearance from the Censors is concerned, it takes hours to get the materials approved by them; and this results in delay in issues of newspapers, thus obviously affecting the circulation thereof. I would like to know from the hon. Minister how many Indian journalists have lost their accreditation—at least as far as Parliament-reporting is concerned, if at all, how many foreign journalists have been expelled, and on what charges from this country; whether facilities like telephone connections were denied to journalists, both Indian and foreign, in the country in the wake of Emergency; and how many journalists were arrested and whether they were arrested for violating the guidelines or they were arrested under MISA for some other activity. On the one hand, we find that the Government is going on with their vendetta against the newspapers. But what is happening in the *"Statesman"*? There, 18 employees have been suspended. The Minister gave an assurance on the floor of the House on 31st March that some action was going to be taken. The only crime of the employees is that they have given evidence before a fact-finding committee; for that reason, they have been suspended and are going to lose their jobs. And, after the Minister's assurance on the floor of the House, the management is expediting the enquiry against them; and the employees are likely to lose their jobs at any moment. I request the hon. Minister to look into the matter. He may also kindly tell us what is the policy of this Government so far as small newspapers are concerned especially with regard to advertisements. Mr. Patil who knows a good deal about journalism and the position of the newspapers, has himself said that a large bulk out of the money made available by the DAVP is monopolized by the *"Times of India"* group of publications. I would like to have a break-up of the advertisement expenses or the advertisement money being spent by the Government; how is it being utilized and what benefit are the small newspapers getting from out of them? You can go on multiplying the large number of publications for the 20-point programme. I am not going into it. I do not mind your utilizing the radio and the TV only for political purposes. But the other political parties and their viewpoints also must get some publicity either through the news media, television or the radio. With regard to the newsprint....

MR. SPEAKER: I think you should conclude.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I am on the last phase of my speech, Sir.

With regard to newsprint, I am told that it is not lifted by a large number of newspapers, either because of a fall in their circulation or because of the poor quality of the newsprint. We would like to know the position from the hon. Minister, because these facts are not known to us.

I would inform the hon Minister that if you really believe that only through censorship you can take this country towards better progress, either from the economic, cultural, social or political point of view, you are suffering from an illusion You cannot go on denying the people of the ordinary rights and then think that the people will be with you.

So, I oppose the grants of the Ministry. I oppose the grants on principle, because these moneys are used for political propaganda, and not for the welfare of the people of the country.

श्री रामसहाय पाण्डे (राजनदगांव)। अध्यक्ष जी, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हू। बधाई इस लिये देता हू कि उन्होने बडी कर्मनिष्ठा, विश्वास और दायित्व के साथ अपने काम को किया है और जो उपलब्धिया प्राप्त की हैं, उन के लिये वे निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं।

श्रीमन्, सब से पहली उपलब्धि विभिन्न समाचार एजेन्सियो को एक स्थान पर ला कर खड़ा करना है। मैं नई "समाचार" एजेन्सी का स्वागत करता हू। अब समाचार के लिये समाचार नही होगा, बल्कि वह समाचार होगा जो सत्यनिष्ठ होगा, जो घटनाओं से मण्डित होगा। हमारी जनता आग्रह कर रही थी कि हमे वह समाचार मिले जो घटनाओ से मण्डित हो, कन्काक्टड (बनाई हुई बातें), झूठ, क्रोध से भरा हुआ वातावरण—इन सब से प्रेरित हो कर जो समाचार छपते थे, उन से जनता ऊब चुकी थी। यह सदन गंगा की गंगोत्री के समान है, इस की पवित्रता महान है। यहां कुछ चुने हुए प्रतिनिधि आपातकालीन स्थिति के पहले जिस प्रकार सत्याग्रह, दुराग्रह, क्रोध, लांछन और आरोपो से यहाँ के वातावरण को दूषित कर रहे थे, उसे कभी भुलाया नही जा सकता, लेकिन आज हम उस वातावरण से दूर, विनोबा भावे के शब्दो और भावनाओ के अन्तर्गत अनुशासन पर्व के नीचे इस सदन की कार्यवाही को चलते देख रहे है—इस का बडा भारी प्रभाव न केवल देश मे बल्कि देश से बाहर भी पडा है।

अभी श्री सोमनाथ चैटर्जी जी साहब ने कहा—हम जनता से कुछ छिपाते हैं। यह बात सच नही है। हम जनता के पास उन्ही भावनाओं को, उन्ही शब्दो को, उन्ही सम्बन्धो को ले जाना चाहते है जिन का सचार सदन से होता है। श्रीमन्, पहले अलग अलग समाचार एजेन्सिया अलग अलग समाचार घडती थी, जिन से सारे देश मे एक ऐसा निराशापूर्ण वातावरण पैदा हो गया था, एक प्रकार का वैक्यूम पैदा हो गया था, ऐसा अनुभव होने लगा था, जैसे हम किसी अधकार मे पडे हो, किसी प्रकार की कोई आशा की किरण दिखलाई नही पड रही थी। एक ऐसी वातावरण पैदा हो गया था जो सच्चाई से दूर था, जिस का घटनाओ से सीधा सम्बन्ध नही था। यदि ऐसे समाचारो का प्रचार और प्रसार होता रहता तो फिर इस लोकतन्त्र का क्या होता? लोकतन्त्र की एक शर्त यह भी है कि जहा लोकतन्त्र हो, वहा अनुशासन भी हो। लोकतन्त्र मे वाणी स्वातन्त्र्य का यह अर्थ नहीं है कि वह गाली का स्वरूप धारण कर ले। गंगा जल का यह अर्थ नही है कि वह नाली का पानी बन जाय। शुद्धता और पवित्रता की इस सदन से जनता अपेक्षा करती है। यही उत्तर मैं श्री सोमनाथ को उन के प्रश्न के उत्तर मे देना चाहता हू।

श्री विद्याचरण शुक्ल जी ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं—उन में सब से पहली

[श्री राम सहाय पाण्डे]

तो यही है कि उन्होंने देश की चार समाचार एजेन्सियों को उन की अपनी इच्छा के अनुसार एक जगह पर एकत्रित कर दिया। और उन की कन्सेंट से, उन के अनुग्रह से इस एक समाचार एजेन्सी का निर्माण हुआ जिस का स्वागत होना चाहिये।

श्रीमन्, जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसी समस्या नही है जिस के ऊपर इस मंत्रालय की नजर न गई हो। आकाशवाणी को लीजिये, हम उस के द्वारा समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इस आर्थिक विकास के संदर्भ मे, जैसे ही कुछ आर्थिक विकास हुआ गाव के लोगो का, सब से पहले उस के मन मे एक जिज्ञासा होती है कि देश मे क्या हो रहा है। देश की घटनाओं के प्रति उस की जिज्ञासा देखते हुए वह ट्रांजिस्टर लेता है और जहा संगीत का रसास्वादन करता है वहा समाचारों के प्रति उस का अनुराग देख कर लगता है कि वह बड़ा जागरूक हो रहा है। इसलिये सच्चाई के साथ। घटनाओ से कडित समाचार उस तक पहुंचना यह एक जागरूकता का लक्षण है।

अभी 20 सूत्री कार्यक्रम की हमने एक रचना की। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में 20 सूत्री कार्यक्रम की जो रचना है उस को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। हमे बड़ी खुशी है यह देख कर कि दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों इस कार्य को बड़ी दक्षता और कुशलता के साथ कर रहे हैं। स्टाफ आर्टिस्ट्स की भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने किसी भी प्रकार की मन में बात न रखते हुए जो सच बात थी उस को वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया।

आखिर 20 सूत्री कार्यक्रम किस के लिये है। 12 सूत्र तो गांवों से संबंधित हैं। 8 सूत्र हैं जिन का सम्बन्ध है शहर के लोगों से। 4, 5 सूत्र-सूत्रों को ले कर श्री संजय गांधी चले, जिस के लिये श्रीमती लक्ष्मीकांतम्मा ने पॉइंट आफ आर्डर किया, जो मेरी राय में व्यर्थ था। मैं समझता हूं कि हर आदमी का दायित्व है, जो देश को आगे बढ़ाने की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ना चाहता हो, कि न मानुषा श्रेष्ठ तरोहिलांके—वह देश को अपने साथ आगे ले चले। ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा होनी चाहिये और यह सदन प्रशंसा के लिये और अच्छे कार्य करने की सराहना के लिये है। इसलिये यदि संजय गांधी का नाम लिया गया तो समय के अनुसार है, उस का औचित्य भी सिद्ध होता है।

अभी माननीय सोम नाथ चटर्जी ने कहा कि हम छिपाते हैं। हम क्या छिपाते हैं? अभी परसों की बात है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पद यात्रा की। हमारे साथ दो, तीन मित्र बैठे हुए टी०वी० देख रहे थे। उन्होने कहा यह कहां छिपाने की बात है, बड़ी स्वतंत्रता के साथ—न कही पुलिस थी, न सेक्योरिटी थी,—एक स्पौन्टेनियस वातावरण के साथ उन्होने अपने कर्तव्य का पालन किया जिस से प्रेरणा मिली और यह आह्वान देश भर को दिया गया, चुने हुए सदस्यों को जो जन प्रतिनिधि बनने का दावा करते हैं कि वह इस नव जागरण के साथ पैदल चले। और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी पदयात्रा के साथ इस का श्री गणेश किया।

आपातकालीन स्थिति के पहले समाचार-पत्रों का जो दृष्टिकोण था, उन का जो व्यवहार था, जो उन का संचालन था, वह शुद्ध नहीं कहा जा सकता। उस में एक कलकालन था, आक्रोश था, घृणा थी और यह घृणा का वातावरण देश में उत्पन्न कर के वह न जाने क्या चाहते थे, मैं नहीं समझ पाया। लेकिन आपातकालीन स्थिति के साथ जैसा अनुशासन हम देख रहे हैं, जिस स्नेह से देख रहे हैं,

जिस कर्तव्य बोध को हम देख रहे हैं उससे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा देश जिस मार्ग की खोज मे था वह मार्ग उस को प्राप्त हुआ। समाचार-पत्रों के प्रतिष्ठानो के सहयोगियो को भी धन्यवाद] दिया जाना चाहिये कि वह इस सूत्र मे आकर के आबद्ध हुए और एक सूत्र मे बंध कर इस देश की सेवा करेगे। विदेशी समाचारपत्रो के लोगो ने जिस प्रकार तोड़ मरोड कर यहा से समाचार भेजे है और अपनी टिप्पणीयो और सम्पादकीय लेखो से देश का गलत बाहर प्रकट किया, उन के इस कार्य की मन्त्री महोदय ने भर्त्सना की है, और श्रीमन मैं भी आप के द्वारा उन की भर्त्सना करना चाहता हू। यह उनका काम नही है कि बताए कि किस प्रकार की शासन पद्धति हमे चाहिये, किस प्रकार की विधि चाहिये, किस प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने के लिये किस प्रकार की प्रक्रिया और शासन व्यवस्था हो, या विधि और प्रणाली बने। इस सब को देखना हमारा काम है, उन का काम नही है। श्री शुक्ल ने ठीक ऐसे विदेशी समाचार पत्रो के प्रतिनिधियो के, जो यहा से इस तरह के समाचार भेजा करने थे, जिनका मन शुद्ध नही था, विचार शुद्ध नही थे, जो अपनी इस स्वतन्त्रता का शोषण करते थे हम को बदनाम करने के लिये, खिलाफ कार्यवाई करके ठीक ही किया है। इसका औचित्य स्वय सिद्ध है। लेकिन एक निवेदन मैं करना चाहता हू। श्री शुक्ल इस बात को समझे कि अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियो के द्वारा जो समाचारो का आदान प्रदान होता है उस मे एक बहुत बडा असन्तुलन है। हमारे यहा से पन्द्रह से बीस हजार शब्दों के संवाद यहां से बाहर जाते है और वहां से चालीस पचास हजार शब्दो के संवाद इस देश मे आते है। हम चाहते कि जब आप इतने क्रान्तिकारी कदम उठा रहे हैं और देश को आप ऊपर उठाना चाहते हैं अनुशासन के द्वारा तो आपका यह भी कर्तव्य होना चाहिये कि जिस प्रकार से आपने सब समाचार एजेंसियों को एक समाचार ऐजसी समाचार, बना दी है इसी तरह से हमारे अपने प्रतिनिधि, समाचार की एजेंसिया भी दुनिया के बडे बड़े शहरों मे हों।

दूर दर्शन के माध्यम से एक नव जागरण की दिशा में कदम उठाया है उसकी भी प्रशसा होनी चाहिये स्टाफ आर्टिस्टस ने भी जिस लगन से उस मे काम किया है और कर रहे हैं उन की प्रशसा होनी चाहिये। मैं देख रहा हू कि बीस सूत्री कार्यक्रम को जो लोकप्रियता मिल रही है और जिस निष्ठा के साथ उस को यहा पेश किया जा रहा है, जिस का सम्बन्ध गरीबी से और गरीबों से है सर्वहारा समाज से है, उन से है जो आज झुग्गियो और झोंपडियों मे रहते है इन्होने उस मे जा कर आज की स्थिति पूछा है, उन से मिले हैं और सही चित्र इन्होंने दूर दर्शन के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत किया है। 2400 गावो को आपने सैटलाइट के द्वारा जोडा है और मैंने देखा है कि इन प्रोग्राम को देखने के लिये पाच दस हजार की भीड लगी रहती है। मैंने अपने क्षेत्र के, राजनन्दगाव के एक गाव मे देखा है, वहा मैं गया था वहा सैटलाइट के द्वारा एक कहानी बताई जा रही थी मानव के उत्कर्ष की कहानी और वह बहुत ही सुन्दर ढग से पेश की गयी थी। मैंने जनता से पूछा कि आपने क्या क्या समझा और आप की क्या प्रतिक्रिया है? सभी ने इसकी प्रशसा की। आदि से अन्त तक मानव की कहानी उसे दिखाई गई थी। जंगली अवस्था, पाषाण युग, नदियो के किनारे लोगो के जा कर बसने की कहानी, खेती करने की कहानी से ले कर वर्तमान युग तक की कहानी प्रस्तुत

[श्री रामसहाय पाण्डे]

की गई थी । यह बहुत ही ज्ञानवर्धक थी । जीवन के तमाम तत्वों का बहुत ही सुन्दर ढंग से चित्रण किया गया था और लोगों के सामने उपस्थित किया गया था । ये जागरण के लक्षण हैं । इस में छिपाने वाली कोई बात नहीं है । जो सच बात है उस को छिपाते हम नहीं हैं । हम जागृति पैदा करना चाहते हैं, लोगों की संकल्प शक्ति को, उन की क्षमता को बढाना चाहते हैं ज्ञान के द्वारा ज्ञान के माध्यम से उन को बताना चाहते हैं कि जो देश के सामान्य नागरिक हैं वही इस देश के भाग्य विधाता हैं, देश का भविष्य उन के हाथ में है ।

दूर दर्शन का जहां तक सम्बन्ध है दुनिया उन्नति कर चुकी है । मैं शुक्ल जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके कि इसके एपेरेटस में अगर कोई कमी है तो एक एक्सपर्ट कमेटी बिठा करके और जो कमियां है उन को वह दूर करवायें श्रव्य और दृश्य दो ऐसी चीजें है जिस से व्यक्ति प्रभावित होता है, समाज प्रभावित होता । आप बहुत से कार्यक्रम देते हैं जैसे कृषि दर्शन । इस के माध्यम से आप किसानो का ज्ञान वर्धन करते है । मैं चाहता हूं कि 2400 गांवो तक ही इसको सीमित न रखा जाय बल्कि इसको और भी फैलाया जाय, इसका और भी प्रसार किया जाय । और जो बडे बड़े गाव है उन तक इसको पहुंचाया जाय और इस काम में देर नही लगनी चाहिये । पैसे की कमी हो तो मैं समझता हू कि वित्त मत्रालय आपको उदारता से धन देगा और हम इसमे आपको समर्थन देगें । इस जन जागरण के कार्य मे, इस सकल्प की पूर्ति मे हम में जो शक्ति है वह आपको प्राप्त होगी ।

फिल्मों की ओर भी आपकी दृष्टि गई है । जब से आपने दायित्व सम्भाला है, इस ओर भी आप ने ध्यान दिया है । मारकाट, हिंसा, क्रोध घृणा, अस्वाभाविक चित्रण जो उपस्थित किया जाता था, और सैक्स आदि को ले कर जो दृश्य उपस्थित किये जाते थे उस से भी देश कमजोर हुआ । मैं चाहता हूं कि स्वस्थ चल चित्र प्रस्तुत कर ने के लिये आप कलाकारों को प्रोत्साहित करें । ऐसे नियम की भी आवश्यकता है जो ऐसे चित्रों के निर्माण में जो धन की आवश्यकता है, वह उन को सुलभ करे ।

13.00 hrs.

छोटे छोटे समाचार पत्रों के बारे मे अभी श्री चटर्जी कह रहे थे । मैं भी चाहता हूं कि छोटे छोटे समाचार पत्रों को उत्साहित और प्रोत्साहित किया जाय । विज्ञापनों की दर से अभी क्या होता है कि बड़े बड़े समाचार पत्रो के विज्ञापन वह लौटा देते हैं । उनको काफी विज्ञापन प्राप्त होते हैं । मैं समझता हूं कि छोटे पत्रों की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये और उन की संभाल की भी आवश्यकता है ।

शक्तिशाली ट्रान्समीटर की भी बडी आवश्यकता है । हम दुनिया के बडे-बड़े देशों की वाणी सुनते है कि वहा क्या हो रहा है, उनके ब्राडकास्ट सुन लेते है, लेकिन अपने ही देश के इतर, सुदूर, कोने, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आदि मे क्या हो रहा है, वह नही सुन पाते है । हम समझते हैं कि हाई पावर्ड ट्रान्समीटर, शक्तिशाली ट्रांसमीटर की भी हमको जरूरत है ताकि हम अपने देश की वाणी और एक दूसरे के कार्यक्रम को अदान-प्रदान कर सकें ।

20-सूत्री कार्यक्रम के प्रचार, प्रयोग, पद्धति और प्रणाली के सम्बन्ध में जो कुछ भी आपने किया है, उसके लिये मैं बहुत-

बहुत बधाई देता हूं और यह चाहता हूं कि आप सफल हों। मैं चाहता हूं कि आपका संकल्प, शक्ति, क्षमता जो कुछ भी है, जिसके द्वारा जन-जागरण का भाव आपने पैदा किया है, सचाई को निकट लाये हैं, जनता के साथ जो सान्निध्य किया है, जो पहले नहीं था, इन आपरेटसों और समाचारों के माध्यम से, इन फिल्मों और दूर दर्शन के माध्यम से और आकाशवाणी के माध्यम से, उन सब के लिये आप बधाई के पात्र हैं।

श्री मान सिंह बौरा (भटिंडा) : अध्यक्ष महोदय, आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर जो बहस हो रही है, मैं समझता हूं कि स मंत्रालय को जब से श्री शुक्ल जी ने संभाला है, उन्होंने इसमें सुधार के लिये काफी मेहनत की है। जिस वक्त इन्होंने इस मंत्रालय का चार्ज संभाला, उस वक्त ऐसा वातावरण चल रहा था कि हिन्दुस्तान के बहुत से प्रतिगामी लोग और वह लोग जो हिन्दुस्तान को आजाद नहीं देखना चाहते थे, उन्होंने यहां बहुत गड़बड़ मचाई हुई थी। उसके बाद कुछ कदम उठाये गये जिनको मैं समझता हूं कि कुछ ठीक भी थे। जिन खबरों के जरिये हिन्दुस्तान में गड़बड़ पैदा हुई थी मैं समझता हूं कि इन कदमों से वह ी है और जो सैंसरशिप इन्होंने लगाया था, वह कुछ तो ठीक था, मगर मैं यह नहीं समझ पाया कि जो मोनोपलिस्ट लोग पहले जयप्रकाश नारायण के पीछे थे वह ओवरनाइट कैसे इनके पास आ गये। हम देखते हैं कि अब भी छोटे और मध्यम अखबारों पर एडवरटाइजमैंट और खबरों वगैरा के बारे में उन लोगों का गलबा है।

12.01 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

जो सैंसरशिप लगाया गया था वह इसलिये था कि ऐसी खबरें न छपें जो हिन्दुस्तान में नुकसानदेह हों और प्रोग्रामों में बाधा डालने वाली हों, लेकिन मैंने देखा है कि 20 सूत्री प्रोग्राम को लागू करने वाली खबरों पर भी इसको वे कर्टेल्मेंट कर दिया गया है।

मैं आपको मिसाल दे सकता हूं। यहां सैंटर में जो खबरें छपती हैं अगर वहीं खबरें पंजाब में अखबार वाले छापना चाहते है तो वहां का सैंसर उनको काट देता है। आप हरियाणा, पंजाब में कहीं भी चले जाइये वहां जो सैंसर का अफसर बैठा होता है वह जो चाहता है वही करता है।

मैंने यह भी देखा है कि जो मच्छर मारने की मुहिम है, उसमें भी कहा जाता है कि मुहिम को काट दिया जाये। वह समझते हैं कि कंपेन की कोई भी बात न छपे। इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं।

मैं यह समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है कि जिसको भी आप सैंसर बनाकर बिठायें उसके दिमाग में यह जरूर होना चाहिये कि उसको क्या करवाना है, उसको साफ मालूम होना चाहिये कि प्रोग्राम क्या है। जो लोग पहले उलट विचारधारा के थे, उनको अगर सैंसरशिप पर बैठायेंगे तो वह कैसे प्रोग्राम को इम्पलीमैंट करवायेंगे, यह बात समझ में नहीं आती है। पंजाब सरकार के सम्बन्ध में मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी वहां सैंसर करने के लिये अफसर हो, उसको चाहिये कि वह कम से कम क्लीयर करे कि क्या करना चाहते हैं।

[श्री मान सिंह औरा]

किसी प्रोग्राम या स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के बारे में जो क्रिटिसिज्म हुआ है, उस को नहीं छापने दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक डिपुटी कमिश्नर कहता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में हम ने 30,000 मकानों के लिये जगह दे दी है। मैं एम० पी० हूं ; मैं वैरिफाई कर के कहता हूं कि उस ने गलत बात कही है ; 30,000 मकान क्या, 3,000 मकानों के लिये भी जगह नहीं दी गई है। मैं गांव गांव घूमता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे साथ चल कर देखें । लेकिन मेरी बात नहीं छापी जायेगी। सेंसर की नजर में डिपुटी कमिश्नर की बात ठीक है, और इस लिए उस ने जो ज्यादा फिगर दी है, उसी को छापा जायेगा। यह जरूरी है कि इस तरफ ध्यान दिया जाये।

कुछ लोग सेंसर को परवाह नहीं कर रहे हैं। मैं आप को एक मिसाल देना चाहता हूं। इलस्ट्रेटिड वीकली आफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है "व्हाट इज हैपनिंग इन बंगलादेश"। शायद आप ने उस को पढ़ा होगा। समझ में नहीं आता है कि यह आर्टिकल कैसे छपने दिया गया है । यह आर्टिकल हमारे मुल्क के इन्ट्रेस्ट के खिलाफ है, सरकार की गाइडलाइन्ज के खिलाफ है। मैं उस में से क्वोट करता हूं :

"Amongst the foreigners, Mr. Samar Sen and the US envoy, Mr. Boster, were reported to be active during the troubled days in November—visiting the Dacca Cantonment frequently. Consequently, Indian and US backing was rumoured for Brigadier Musharraf and General Rahman respectively."

मुझे पता चला है कि वीकली का एडीटर किसी मिनिस्टर की गंदी फोटो छाप कर उन को खुश कर देता और फिर वह जो चाहे लिखता है। कोई उस को पूछने वाला नहीं है मैं आप को एक मिसाल देता हूं। उस ने पंजाब में अपने एक नजदीकी रिश्तेदार को पब्लिक सर्विस कमीशन का मैम्बर बनवा दिया है। उस अफसर को सब जानते हैं। वह ऐसा अफसर था, जिस के बारे में यह समझा जाता था कि वह वक्त से पहले रिटायर कर दिया जायेगा। वह मोस्ट करप्ट आदमी था। पंजाब का बच्चा बच्चा उस को जानता है। वीकली ने चीफ मिनिस्टर की फोटो छाप दी, और उस शख्स को कमीशन का मैम्बर बना दिया गया। वीकली जो चाहे, वह लिखता है। पता नहीं उस को कैसे छपने दिया जाता है।

सरकार की पालिसी है कि दोस्त मुल्कों के खिलाफ अखबारों में कुछ न छापा जाये। आज हम देखते हैं कि बिड़ला और टाटा के मोनोपोली पेपर्ज सोवियत यूनियन के खिलाफ वैस्ट से मिली हुई खबरें और स्टोरीज छाप रहे हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब जवाब देते हुये इस पायंट को जरूर लें कि वह इस बारे में क्या करने जा रहे हैं ?

सरकार डीलिंकिंग की बात बहुत अरसे से कह रही है। मैं तो यह समझता हूं कि सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठायेगी। के० के० बिड़ला पहले हिन्दुस्तान टाइम्स का मालिक था, अब वह इण्डियन ऐक्सप्रेस का भी मालिक बन गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि डीलिंकिंग के बारे में फैक्ट फाइंडिंग के बारे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो सिफारिश की है, क्या सरकार उस को मान रही है। इस रिपोर्ट में लिखा है :—

"....Pending the adopting and implementation of the requisite legal measures, it will be desirable to

take steps for checking the use of newspaper profits for non-newspaper purposes".

क्या सरकार ने इस बात को चैक करने के बारे में कोई कदम उठाया है ? सभी जानते हैं कि ये बड़े बड़े अखबार वाले अपने कुनबे के लोगों को बड़ी बड़ी तन्ख्वाहे देते हैं और वे मुलाजिमों की कोई परवाह नही करते हैं। 20-प्वाइंट प्रोग्राम से भी कहा गया है कि मनेजमेंट में मुलाजिमों को हिस्सा दिया जाएगा। मिनिस्टर साहब को बताना चाहिये कि क्या अखबारों के बारे में इस सिलसिले में कुछ किया गया है या नही।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 20-प्वाइंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिये पैम्फलेट और पोस्टर बांटे गये हैं और डाकुमेंटरी फिल्म्ज दिखाई गई है। यह बडी अच्छी बात है। लेकिन ये डाकुमेंटरी फिल्म्ज गांवों मे नहीं दिखाई जाती है। अंग्रेजी के मेट्रोपालिटन अखबारों का सारा सर्कुलेशन 94 लाख है। 94 लाख सर्कुलेशन हमारे 60 करोड़ के मुल्क मे है और इनके जरिए आप चाहते हैं कि प्रोग्राम लोगो के पास पहुंचें तो वह पहुंचता नही है। इसमे ज्यादा गिनती तो इंग्लिश के पेपर्स की है। जो छोटे पेपर हैं या लैंग्वेज के पेपर हैं जिन के जरिये आपके प्रोग्राम लोगो तक और गांवों तक पहुंच सकते हैं वे बेचारे तो मर रहे हैं। उनको कैसे जिन्दा रखना चाहिये। इस पर भी आपको जरा ध्यान देना चाहिये।

इसी तरह ऐवर्टाइजमेंट का मामला है। मै हर रोज देखता हूं बड-बडे अखबार एडवर्टाइजमेंट से भरे रहते है। इस के लिए कोई कानून है या नही कि इस को कैसे रेगुलेट करना हैं ? ये बडे-बडे अखबार जितने हैं वे तो सारे ऐडवर्टाइजमेंट से ही भरे रहते हैं। बडे-बडे ऐडवर्टाइजमेंट्स उन मे आते हैं जो छोटे छोटे अखबार हैं वे बेचारे बुरी हालत में हैं। कोई घाटे मे चल रहे है कोई अच्छी तरह से चल नहीं पा रहे हैं। उनको चलाने के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

आप एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि जो हमारी पालिसी के साथ चलते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिये। लेकिन मुझे यह पता चला है कि जो 20- प्वाइंट प्रोग्राम को लागू करवा रहे हैं उनके ऐडवर्टाइजमेंट डी० ए० वी० पी० की तरफ से बन्द हैं और जो बड़े बड़े मोनोपलिस्ट पेपर हैं उनको ऐडवर्टाइजमेंटस मिल रहे हैं। डेढ़ साल से पहले की बात है यह कैम्पेन चला, कौन पेपर आपके साथ था और कौन आज साथ है, यह भी देखना होगा।

यह जो पैम्फलेट्स वगैरह निकलते हैं ये रीजनल लैंग्वेजज में भी जाते हैं या नही ? पब्लिसिटी का यह हाल है कि आप के प्रोग्राम गांवों मे बहुत कम पहुंचते हैं क्यों कि स्टेट्स के पब्लिसिटी-डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेंगे तो आपके मिनिस्टर जाएगे तो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट जाएगा, अगर मिनिस्टर नही हैं तो कोई पब्लिसिटी वाला गांव मे नही जाता है। इसके लिये आप क्या करने जा रहे हैं ?

सबसे जरूरी बात यह है कि रेडियो के जरिये आप हर एक जगह, इंटीरियर मे भी जा सकते हैं। इसके लिये आल इंडिया रेडियो मैं कैसे लोगों को बुलाया जाय और इसके लिये और क्या किया जाय इस पर मैं समझता हू आप विचार करेंगे। टी० वी० आपने सस्ता किया यह अच्छी बात है। लेकिन रेडियो सस्ता करना चाहिये था, ट्रांजिस्टर सस्ता करना चाहिये था। जितना रेडियो सस्ता करेंगे, ट्रांजिस्टर सस्ता करेंगे उतना ही उनके जरिये आपका प्रोग्राम हर जगह पहुंचेगा। अखबारो के जरिये सब जगह नही पहुच सकता। वह तो कुछ सेलेक्टेड लोगो तक ही रहेगा।

इसी तरह न्यूजप्रिंट का मामला है। आपका नेपा न्यूजप्रिंट है, उसकी क्वालिटी अच्छी नही है। सब लोग उसकी कम्प्लेंट करते हैं। उसकी क्वालिटी अच्छी बनाने के लिये आप कुछ कर रहे है या नही ? मैं नहीं समझता कि हिन्दुस्तान में पेपर के लिये

[श्री प्रताप सिंह बौरा]

बाहर जाने की जरूरत है । हमारे पास रा मैटीरियल है, सब कुछ है, मिलें और लगा सकते हैं। बड़े बड़े पेपर वाले तो इम्पोर्ट कर सकते है । छोटे पेपर इम्पोर्ट नहीं कर सकते है । फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक आपने बनाई है। मेरा सुझाव है कि स्पेशल रिजर्वेशन फार स्माल ऐंड मीडियम न्यूज-पेपर्स आपको करना चाहिये । उनको सिर्फ 55 हजार टन की जरूरत है। वह आप कैसे पूरा करेंगे यह मैं जानना चाहता हू । बड़े बड़े पेपर वाले तो मंगवाते रहते है क्योंकि वे तो इतना मुनाफा कर लेते है लेकिन छोटे और रीजनल लैंग्वेज के जो पेपर हैं उनके लिये न्यूजप्रिंट का इंतजाम आपको जरूर करना चाहिये क्योंकि इंग्लिश पेपर तो 25 प्रतिशत हैं केवल, बाकी तो लैंग्वेज पेपर्स है ।

वर्किंग जर्नलिस्टस के मामले पर भी आप ध्यान दे । उनके लिये जो न्यूट्रलाइ-जेशन का फार्मूला है वह भी लागू नही किया है। महगाई 135 परसेंट बढ़ी है और उनके वेतन मे वृद्धि केवल 50 परसेंट की गई है । इसके ऊपर भी आपका ध्यान देना चाहिये ।

न्यूज ऐजेंसीज की बात पहले आई है । यह बड़ी अच्छी बात है कि अब आपने एक न्यूज ऐजेंसी कर दी है लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि वे लोग जिनकी वजह से ये न्यूज ऐजेंसीज खराब हो गई थी, वे आर० एस० एस० और बैन्ड आर्गेनाइजेशन्स के लोग उसमे आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हू कि उनकी स्क्रीनिंग आपने की है या नही। जिनके खिलाफ यहां हमने एक दफा कहा था, जो बैन्ड आर्गेनाइजेशन के लोग हैं वे इसमे आ रहे हैं । दूसरे, कुछ स्माल न्यूज एजेंसीज भी चल रही हैं, उनके बारे मे क्या आपकी पालिसी है वह भी आप बताये । यह समाचार एजेंसी जो आपने बनाई उनमे एम्प्लाईज को मैनेजमेंट में रिप्रेजेन्टेशन देने का क्या प्रोग्राम है ? मैं समझता हू यह भी आपको करना चाहिये ।

अब मैं सांग ऐंड ड्रामा डिवीजन पर आना चाहता हू । यह बहुत जरूरी है । यहा पर बहुत बडा सांग ऐंड ड्रामा डिवीजन है लेकिन आप इसकी यूनिट्स रीजीनल लैंग्वेजज मे कब तक बनायेंगे और उसकी शाखायें खोलेंगे-यह मैं जानना चाहता हू । स्टेटस मे जो सांग ऐंड ड्रामा डिवीजन्स हैं वह तो सिर्फ मिनिस्टर्स को एन्टरटेन करने के लिए ही हैं इसलिये अगर आप गावों तक प्रोग्राम पहुंचाना चाहते है तो उसके लिये जरूरी है कि हर लैंग्वेज मे इसकी यूनिटस् बनाये । साथ ही मैं कहना चाहता हू कि मुझको मालूम हुआ है, तीन साल पहले मैंने इसके जो इनचार्ज हैं कर्नल गुप्ते उनके खिलाफ चार्जेज लगाये थे लेकिन उनको आप एक्सटेंशन दे रहे है और जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है । उनके खिलाफ बड़े सीरियस चार्जेज लगे थे और मुझे यकीन दिलाया गया था कि इस सिलसिले मे कुछ किया जाएगा ।

इसके बाद मैं कहना चाहता हू कि हमारे अमृतसर टी० वी० मे पंजाबी प्रोग्राम देने शुरू कर दिये हैं लेकिन पंजाबी प्रोग्राम आप दिल्ली मे बना रहे हैं । एक आर्टिस्ट को इतनी दूर आने जाने मे तीन सौ रुपये लगते हैं और जो आपके डायरेक्टर हैं उनको एक साल मे एक हजार रुपया खर्च करने की पावर है । इस तरह से वे एक आर्टिस्ट आपको तीन दफा बुला सकते है । अगर वहा पर आप बनायेंगे तो आर्टिस्ट आपको सस्ते मिलेंगे । साथ ही डायरेक्टर की जो खर्च करने की पावर है वह भी बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाकर दो हजार करना चाहिये ।

टी० वी० को जो अलग किया गया है तो उसके जो मुलाजिम हैं उनके लिये आप क्या कर रहे हैं , इस सिलसिले मे कुछ पता नहीं है । पता नहीं है उनकी सर्विसेज का क्या

हो रहा है ? टी० बी० के कर्मचारी ज्यादा टैक्निकल और योग्य है। साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हू कि जालधर मे जो स्टेशन आपका बन रहा है उसमे जल्दी करनी चाहिये। आप कोई रैटेड बिल्डिंग ही ले लें और प्रोग्राम देना शुरू कर दें। इसमें कोई मुश्किल बात नही है।

इसी तरह से एक ओ० बी० वैन जो पंजाब के लिये थी वह वेस्ट बगाल चली गई। शायद पजाबके लोगो ने उनकी जरूरत नही समझी होगी लेकिन वहा पर पाकिस्तान के टी० बी० प्रोग्राम्स को काउटर करने के लिये उसकी बहुत जरूरत है। अमृतसर टी० बी० को ओ० बी० वैन प्रोवाइड करनी चाहिये।

तिरुनेलवेलि, तमिलनाडु मे एक स्टेशन है जो चार दिन हफ्ते मे काम करता है उसको भी बढाने का इन्तजाम करना चाहिये। इसी तरह से बम्बई मे एक चिल्ड्रेन सोसायटी है जिसके डायरेक्टर के खिलाफ चार्जेज लगाये गये हैं कि वहा पर जो मुलाजिम हैं उनको पेनलाइज किया जा रहा है—इसको भी देखना चाहिये।

इसी तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ जूनियर आफिसर्स को सेलेक्ट किया था लेकिन आपने डिपार्टमेंट मे आज तक उनको एप्वाइट नही किया है। उनका सेलेक्शन हो गया है, मैं समझता हू कि यू० पी० एस० सी० उनका सेलेक्शन करता है तो उनको भी पोस्ट देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इन सारी बातो पर गौर करेंगे।

श्री सी० के० गोतम (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं आपको धन्यवाद देता हू कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। दूसरा धन्यवाद मत्रालय को है। मंत्री महोदय ने अपने मत्रालय मे बहुत प्रगति की है। जो पुराना तरीका था उसको बदला गया है। हमारा जो बीस सूत्री कार्य-क्रम है उसको हर तरह से और हर पहलू मे कार्यान्वित करता है। इस ख्याल से इस मत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है और हर बात मे, हर पहलू मे प्रगति की है। जो पुरानी रूढिया चल रही हैं थी, उनमे तब्दीली पैदा की है। हमारे यहा रेडियो और टेलिविजन को, यद्यपि टेलिविजन बहुत ज्यादा नही हैं, जो सफलता मिली है, उतकी सफलता शायद दूसरी स्टेट्स को नही मिली है। हमने देखा है—जब टेलिविजन पर हमारे नेता लोग आते हैं, खास कर हमारी प्रधान मत्री जी जब टेलिविजन पर आती हैं, जनता को सम्बोधित करती हैं, उसका बहुत बडा प्रभाव जनता पर पडता है, जनता उनकी बातो को बहुत ध्यान से सुनती है। जहा तक कि कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं कि वे दुर्गा की साक्षात अवतार हैं और हमारे सामने साक्षात बोल रही है, हम को सम्बोधन कर रही हैं— इन बातो का जनता पर बातो का जनता पर बडा भारी असर पडता है।

यह ठीक है कि टेलिविजन हमारे यहां बहुत थोडा है, लेकिन रेडियो तो कोने-कोने मे फैला हुआ है, इसके जरिये सब समाचार गावो तक पहुचते हैं। आप यह जानते हैं कि हमारे देश की 70-75 आबादी गांवो मे ही रहती है, जब वे रेडियो सुनते हैं, खास कर खेती-बाडी के कार्यक्रमो को किस्से कहानी के रूप मे पेश किया जाता है, सवाल जवाब के रूप मे पेश किया जाता है, बीज कैसे होने चाहिये, उर्वरक कैसा होना चाहिये, कौन सी जमीन का किस प्रकार के बीज और उर्वरक की जरूरत है, जमीनों के बारे मे उनको जो जानकारी मिलती है—इससे उनको बहुत लाभ होता है, वे अपनी खेती-बाडी में उन बातो का प्रयोग करते हैं और लाभ उठाते है।

इसी तरह से परिवार नियोजन को लीजिये—पहले जब हम गांवो में जाकर बोलते थे, तो स्त्रियां अपना मुह ऊपर नहीं

[श्री सी० डी० गौतम]

उठाती थीं, यह कहा जाता था कि यह व्यक्ति अभद्र बात बोलता है। परिवार नियोजन की बात कहना उनके ख्याल में अभद्र बात थी, लेकिन आज हमारे रेडियो और टेलिविजन के प्रसारण के कारण अब ये बातें अभद्र नहीं समझी जातीं, महिलायें भी खुले-आम इसके बारे में बातें करती हैं, बल्कि आपरेशन के लिये तैयार होती हैं, आपरेशन करवाती हैं।

दहेज प्रथा के विरुद्ध जो प्रचार हमारे रेडियो और टेलिविजन से हुआ, उसका यह परिणाम निकला कि पहले जो बड़ी बड़ी रकमें लोग दहेज में लेते थे, आज कई युवक और युवतियां इस बात के लिये तैयार हो गये हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वे न दहेज लेंगे और न दहेज देंगे। इस प्रकार की भावना का समाज मे फैलना एक बहुत बड़ी बात है।

छुआ-छात के बारे में आप जानते हैं—हमारे देश में उसका एक बहुत बड़ा बढ़ंगा रूप था, लेकिन आज सब एक साथ बैठकर खाते हैं, यह समझ कर कि दूसरा व्यक्ति हरिजन है, अब उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। शहरों में तो ऐसा पहले से ही था, लेकिन अब तो यह हमारे गांवों में हो गया है। जहां तक धर्म निर्पेक्षता का सवाल है—जनता इस बात को समझ गई है कि अगर किसी का कोई खास धर्म है और उसको वह मानना चाहता है तो अपने घर में माने। जहां तक राज्य का सवाल है—राज्य किसी भी धर्म को मान कर नही चलता, उसके लिये सब नागरिक समान हैं। तो इसके लिये मैं मंत्री जी को और उनके मंत्रालय को तथा अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और मान्यवर, आपको भी धन्यवाद देता हूं।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष जी, सूचना और प्रसारण का एक बहुत बड़ा महकमा है, करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया जाता है। यह प्रचार का साधन है, और प्रचार का साधन होना भी चाहिये। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह वन वे ट्रैफिक बन चुका है। बाहर से खबर आती है लेकिन अन्दर से नहीं जाती। हिन्दुस्तान के कितने ही पत्र और पत्रिकायें पढ़ने को मिलती हैं जिनमें अच्छी प्रचार की सामग्री होती है। लेकिन हमारे पार्लियामेंट की बात तो वही मिलेगी जैसे इधर से जाओ और उधर से मत आओ। तो वन वे ट्रैफिक का मतलब यही होता है।

आपने सबसे पहले अखिल भारतीय प्रस परिषद् पर काबू किया और अन्य भी जो प्रचार और प्रसार के साधन थे उन सबको अपने कब्जे में आपने ले लिया। उन को सरकारी साधन बना दिया और सरकारी साधन कई तरह से बनाया। यानी 20 सूत्री कार्यक्रम ही आप लें यह कार्यक्रम कई सालों से चलता आ रहा है और हिन्दुस्तान का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो किसी न किसी कार्य में व्यस्त न हो। लेकिन आज केवल तीन, चार प्रचार साधनों पर ही हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय चल रहा है। एक तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम है, जब भी देखोगे यही चलेगा। दूसरा यह कि आज इतने डाकू पकड़ लिये, एम० आई० एस० ए० और डी० आई० आर० में गिरफ्तार कर लिये। छोड़ने का नाम नहीं। आज से तीन साल पहले भी पकड़े थे विदेशी मुद्रा और काले धन के सिलसिले में। कहने का मतलब यह कि यह सब ऐसा प्रचार है जिसका दुनिया में कोई सार नहीं है। इसी तरह से आप गांवों में सेटेलाइट द्वारा प्रचार कार्य कर रहे हैं। 6 राज्यों के अन्दर आपने 2400 टी० वी० से. लगाये हैं। लेकिन वह कौन से टाइम पर कृषि कार्य बतलाते हैं, कब संगीत करते हैं और कब खबर देते हैं, किसी ने जाकर कभी देखा भी भी [illegible] आपको कोटा की बात बताता

चाहता हू, बौम्बे रोड पर आप देखें, कौन से टाइम पर दिखाते हैं। अव्वल तो उन सैटों में आवाज ही नही आती है, केवल भन्नाटा आता है जैसे हवाई जहाज उडना है ऐसी आवाज आती है। तो ऐसे पैसे बरबाद करके और वह भी दूसरो की सहायता से प्रचार साधन बनाये जिसको कोई देखने वाला नही है, क्या फायदा है? आपको इस ओर देखना चाहिये कि समय क्या चुना गया है।

कृषि जगत कार्य साढे पाच और सात बजे के बीच होता है जिस वक्त को किसान खेत मे रहता है और उसकी औरत भी खेत में रहती है। आजकल गेहू के दिन है, फिर चावल के, उसके बाद बाजरा के, मक्का के दिन आ जायेंगे। सुनेगा कौन आपकी प्रोग्राम को? टी० वी० सैट खाली पडे रहेंगे। इसलिये समय के अनुसार परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। सर्दियो के अन्दर साढे पाच बजे दिन अस्त हो जाता है, और गर्मियों मे साढे सात बजे और किसान घर पर तब आता है जब वह अपने खेत के काम से निपट जाता है। तब वह कही सुन सकता है। अभी यह होता है कि किसान जब अपने खेत मे होता है तब आप अपना प्रोग्राम बाजार मे बजाते हो। तो इसको कौन सुनेगा। इसलिये समय के अनुसार प्रोग्राम को बदला जाय। और समय बढाइये। कार्यक्रमों का ऐसा समय बनाइये जब कि किसान घर पर हो।

एक बात मैं और कहना चाहूगा। आज इतने सालों से कोटा क्षेत्र से रेडियो की माग हो रही है। वहा बिजली की कोई कमी नही है। परमाणु बिजली वगैरह भी बनी हुई है। हम बिजली गुजरात वगैरह दूसरे क्षेत्रों को दे रहे हैं लेकिन कोटा को रेडियो स्टेशन से नही मिलाया जा रहा है। उधर भोपाल मिलता हैं, जयपुर मिलता है, जयपुर से उदयपुर, जोधपुर मिलते है, बीकानेर मिलता है। कोटा ने ऐसा क्या बिगाड दिया कि अजमेर, कोटा, झालावाड नहीं मिल सकते? इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

एक बात मैं और कहूंगा। राजस्थान के संगीतज्ञ वहीं बूढ़े होकर मर जाते हैं, उनको दिल्ली मे लाकर उनके प्रोग्राम नहीं किये जाते। उनको बडी इच्छा होती है कि उनके आल इंडिया रेडियो पर प्रोग्राम हों। दिल्ली में ठेका तो सिफारिशियों ने ले रखा है। एक दफा गुजराल साहब ने यहां सदस्यों के लिये कुछ कव्वाल बुलवाये थे और उनका प्रोग्राम करवाया था। उनसे अच्छी कव्वालिया तो हम अजमेर में सुनते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे सिफारिशियो को दिल्ली मे भर रखा है जिनको संगीत का कोई रियाज हो नही, तानपूरे का कोई रियाज हो नही जो खाली हारमोनियम की भन्नन बजाया करते है। उन्ही को साढे सात सौ रुपया मिल जाता है। आपने सिफारिशी टट्टुओं को भर रखा है। भर्ती करते समय उनको संगीत की परीक्षा लीजिये। हमारे राजस्थान मे अच्छे अच्छे संगीतज्ञ हैं। मुझे भी संगीत का ज्ञान है। मैं तो आपके लोगों को देखकर ताज्जुब मे रह जाता हूं।

आप ने छोटे पत्रों को विज्ञापन देना बंद कर दिया है। आपकी यह धौंस है कि जो आपके खिलाफ हो उसे मत दो। आपत्कालीन स्थिति का मतलब यह नही होता। आपत्कालीन स्थिति का मतलब यह होता है कि देश के अन्दर कोई गडबड पैदा न करे। इसके अन्तर्गत आप अपना काम कीजिए। यह नही कि मदरलैंड को बन्द कर दिया। उसने ऐसा कौन-सा कसूर किया था। आप उस पर सेंसर बिठा सकते थे। अगर पार्लियामेंट में अट शट हम बोलें तो उसको सेंसर बोर्ड देख सकता है। आप ने मदरलैंड को जिन्दगी भर के लिए, बंद कर दिया। एक दफा हम ने मिनिस्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

आपको इससे क्या लेना देना है। आप तो पब्लिक से चुन कर आये हो, आप पार्लियामेंट में बात करो। सरकार हमारी है। हमें मंजूर होगा तो हम रेडियो में भी देंगे, पेपर में भी देंगे। यह सेंसर बोर्ड का काम नहीं है। आप ने बड़े-बड़े पत्रों को भी डांट दिया। सेंसर बोर्ड को तो इतना चाहिए कि जो देश के विपरीत काम करे, देश के विपरीत बोले उसे बंद करो। अगर देश के विपरीत कोई काम करता है तो आपके पास पुलिस है, वह उसे अरेस्ट कर सकती है। यह सेंसर का काम तो नहीं है कि आजादी को खत्म कर दिया। आजादी को खत्म करने से देश का काम तो चलने वाला नहीं है। अगर हम देश के खिलाफ काम करें, बीस सूत्री कार्यक्रम के खिलाफ काम करें तो आपके पास पुलिस बैठी है, वह हमें पकड़े। सूचना और प्रसारण का तो यह काम नहीं है कि हमारे खिलाफ आवाज उठाये। रात दिन रेडियो प्रचार करता रहता है कि हम जनसंघ के टूटी गये और कांग्रेस में मिल गये। उन्हें मिलने को कांग्रेस ही मिली है। जो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह भर्ती होते हैं उनके बारे में भी तो रेडियो कहे। रेडियो एक झूठ का प्रोपेगण्डा बन गया है। यह अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सूचना और प्रसारण का काम देश सेवा है, व्यक्तिगत सेवा नहीं है। जितना भी प्रोग्राम हम देखते हैं वह सारा का सारा व्यक्तिगत होता है।

गन्दे साहित्य की बात लीजिये। आप किसी भी स्टाल पर जाकर देख लीजिए, 95 परसेंट साहित्य में औरतों के गाल चूमते हुए आप देखेंगे। 95 परसेंट साहित्य औरतों के फोटो से भरा होगा। वे जो चित्र होते हैं वे बहुत ही भद्दे होते हैं, बुरे होते हैं। आपका यह भी काम है कि आप बाहर जा कर इस तरह की चीजों को भी देखें और इन पर रोक लगायें।

विदेशों में रेडियो और टी० वी० से लोगों को शिक्षित करने का काम किया जाता है। यहां पर टी० वी० पर आपको ऐसे ऐसे प्रोग्राम देने चाहियें कि बच्चों का भविष्य बन सके, काम धंधों के प्रति उनकी रुचि जागृत हो सके, काम धंधे वे सीख सकें, इंजीनियर आदि बनने में सहायता उनको मिल सके। इस तरह के प्रोग्राम देना तो दूर रहा आप ऐसे ऐसे फोटो देते हैं, ऐसे ऐसे चित्र दिखाते हैं कि उनका बुरा असर बच्चों पर पड़ता है।

जो कैमरामैन हैं वे अभी तक डेली बेसिस पर चल रहे है। उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। इस चीज को आप देखें। कब तक यह ठेके वाला काम चलेगा। उनको आप परमानेंट करें।

मैं चाहता हूं कि कोटा को आप से मिलाए। गंदा जो साहित्य है, उसको आप बन्द करें। मदरलैंड पर जो आपने प्रतिबन्ध लगाया है, उसके खिलाफ जो आपने कार्रवाई कर रखी है, उसको आप हटाए और उसे चालू होने दें।

श्री हरी सिंह (खुर्जा) : [सदन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा चल रही है। मुझे इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन ही नहीं बल्कि प्रशंसा करने को मजबूर होना पड़ रहा है वह इस वास्ते कि इस विभाग ने ऐसे कार्य किए हैं जिन से देश के नव निर्माण की जो प्रवृत्तियां चल रही हैं, जो प्रवृत्तियां देश को ऊंचा उठाने की चल रही हैं उसकी सही तसवीर इसने जनता के सामने रखी है। इस मंत्रालय ने प्रेस के सम्बन्ध में जो नये कानून बनाये हैं उनकी भी आवश्यकता निर्विवाद थी। सारी न्यूज एजेन्सियों को समाप्त करके एक न्यूज एजेन्सी बनाई है वह भी उचित है। फ्रांसिस बीकन ने प्रतिष्ठित आदमी के बारे में कहा है कि वह तीन तरह का नौकर होता है। "

"servant of the Sovereign State, Servant of fame, Servant of busi-

आज के वक्त में अगर वह होते तो वह यह भी कहते कि समाज का जो प्रतिष्ठित आदमी है उसको प्रेस का भी नौकर होना चाहिए। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर प्रेस वाले अपने पर उतर आयें तो हर भले आदमी की इज्जत बिगाड़ कर रख देते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी इन अखबार वालों की बहुत खुशामद दरामद करनी पड़ती है। भले आदमी को जब अखबार वालों द्वारा ब्लैक मेलिंग किया जाता है तो आख मूद कर चुप रह जाना पड़ता है। बड़े गन्दे तसवीर लोगो के सामने ये अखबार वाले पैसा ऐंठने के लिए पेश कर देते हैं। थाने में ये लोग चले जाते हैं और किसी इनईम्पाटेंट आदमी से कोई रिपोर्ट लिखा देते हैं। उसको छापने की धमकी देते है। यदि पैसा नही मिला तो यह पत्रकारगण उस रिपोर्ट को ज्यो की त्यो छाप देते है। इनवैस्टीगेट तक करने की कोशिश नही करते हैं। असल मे तो जब पुलिस इनवैस्टीगेशन कर लेती है तभी सच्ची बात का पता चलता है कि आया उस व्यक्ति ने डाका डाला है, कोई जुर्म किया है, किसी का चरित्र हनन किया है। इस तरह के समाचारो मे ससद् सदस्यो के परिवार वालो तक को नही बख्शा जाता है। लिख दिया जाता है कि फलां सदस्य के परिवार के लोग भी इनमे शामिल बताये जाते हैं। इस तरह से उनकी सारी परसनैलिटी को ये डैमेज कर देते हैं। इस वास्ते मैं समझता हू कि चरित्र हनन के विरुद्ध जो नये कानून बनाये हैं, वे बहुत जरूरी थे। दिल्ली मे जो संवाददाता हैं, पत्रकार हैं, उनके एजुकेशन का स्तर, उनके मारेल्ज तो काफी ऊंचे हैं, अच्छे पढ़े लिखे वे हैं लेकिन जिला लेवेल पर जो बड़े अखबारो के लोग हैं उनमे ऐसे भी हैं जिनको एम्बैजलमेंट करने के कारण नौकरी से निकाला जा चुका है, जिन को सजाए तक हो चुकी हैं और वे एजेंसियों के संवाददाता तक बने बैठे हैं। दिल्ली मे तो इन संवाददाताओ की तनख्वाह हजार बारह सौ होती होगी लेकिन जिलो मे इनकी आमदनी के हिसाब होती है। पाच हजार रुपये तक भी ये कमा लेते हैं। मुकदमो मे इनका दखल रहता है, अफसर लोग इनको चिलमे भरते हैं, सारे अधिकारीगण इनकी खुशामदें करते हैं, मत्री लोग भी इन अखबार वालो के हाथ मे थे। शुक्ल जी ने जो नियम बनाये हैं, कानून को बदला है यह वाकई मे हिन्दुस्तान के नागरिको की इज्जत बचाने के लिए बहुत आवश्यक था। प्रेस सम्बन्धी नये कानूनो ने गैरजिम्मेदार पत्रकारो पर एक अकुश लगा दिया है।

हम तो स्वय जानते हैं। हमारे यहां दो-तीन पत्रकार हैं। हम देखते हैं इनके जिले मे कुछ खास आदमी हैं उनका ही प्रेस मे नाम भेजा जाता है। दूसरा कोई कितना भी बड़ा काम कर ले, हजारो की भीड इकट्ठी कर दी जाय तो भी अखबारो मे नाम नही आता है। दूसरी तरफ जो लोग उन पत्रकारो की गुड-बुक्स मे हैं, वह कुछ भी काम न करे, उनकी तस्वीरे छप जाती हैं, फोटो छप जाते हैं और उनका नाम छप जाता है। सारे भारत मे उनका चर्चा हो जाता है। तो ये पत्रकार देवता को शैतान और शैतान को देवता बना देते थे। इस मत्रालय ने जो स्वस्थ पत्रकारिता के लिये जो यह काम किया है, वह प्रशसनीय है, वह उचित है। मैं मत्री महोदय का किन शब्दो मे धन्यवाद करू, मेरे पास शब्द नही हैं उनके इस कार्य के लिये।

आप जानते हैं कि अखबार वालो के बारे मे नेपोलियन ने क्या कहा था—

"I can face six bulletmen but I cannot face one single newspaper-man."

जो बात नेपोलियन ने कही थी वह सच थी, और उसका असली रूप यहा दिखाई पड़ता था। आप जानते हैं कि हमारे देश मे विदेशी ताकतो ने अखबार वालो मे से कुछ अखबार वालो को अपनी जेब मे ले लिया था। ये लोग न्यूज और समाचारो की तोड़मरोड़ कर हिन्दुस्तान की तस्वीर को इतनी बुरी तरह

[श्री हरी सिंह]

से पेश करते थे कि मालूम पड़ता था कि जिन लोगों को जनता ने चुना है, जिन्हें जनता ने शक्ति दी है, जो मेहनत करके देश का नक्शा बना रहे हैं, नई बुनियाद डाल रहे हैं भावी हिन्दुस्तान की, उनकी तस्वीर अखबारों में इस तरह देते थे कि जैसे वे लोग दुनिया में सबसे खराब हैं, उन्हें देश व जनता से कोई प्रेम नहीं हैं। जो चौबीसों घंटे देश को उन्नत बनाने मे मेहनत करते थे उनके बारे में वे पत्रकार लोग अपने एक कालम में 2 पैसे की स्याही से उन्हें सबसे बुरा आदमी बनाकर पेश करते थे। मैं कहना चाहता हूं कि प्रेस को ठीक ढंग से चलाने के लिये सरकार ने जो कदम उठाया है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है और इसकी आवश्यकता थी चूंकि स्वतंत्रता को, लिबर्टी को लाइसेंस नहीं बनाना चाहिए। बाईबल में कहा है—

"In the name of liberty, there should be no crime."

प्रेस वाले और अपोजिशन के लोग प्रेस की लिबर्टी के बारे मे चिल्लाते है लेकिन लिबर्टी का सहारा लेकर प्रेस वालों ने देश में एक विषाक्त वातावरण बना दिया था, बहुत से लोगों को अनाथ बना दिया। पुलिस वालों से दोस्ती, अखबार वाले नाराज हो गये तो जो चाहे कर देते हैं। अखबार वालों को सरकार ने इतनी बड़ी ताकत दे दी थी। उसका प्रयोग उन्होंने देश के खिलाफ प्रचार करने में किया। 25 साल तक हम ने देखा कि अखबार वालों ने उसका मिसयूज किया है। सैंसरशिप जिलों से निकलने वाले अखबारों पर पूरी तरह से कारगर नहीं हो रही है। वे अब भी अपनी पुरानी चाल चल रहे हैं। अतः सैंसरशिप उन पर भी सख्ती के साथ लगाना चाहिए।

जिले के लेवल पर आप देखिये, जिसको कुछ मालूम नहीं, जिसके पास कोई पैसा नहीं, हाई स्कूल तक पढा नहीं और वह दो पन्ने का एक अखबार निकालने लगा तो वह एकदम बहुत बड़ा आदमी बन गया। एम०एल०ए०, एम०पी०, कलैक्टर और सभी अफसर उससे डरते हैं क्योंकि उनको डर होता था कि उनकी मिट्टी पिट जायेगी यदि उस अखबार वाले ने उनके खिलाफ कुछ निकालदिया। तो जो स्वतंत्रता मिली थी, उसका मिसयूज इन्होंने किया। जो लिबर्टी इनको दी गई थी, जो हाई स्टैंडर्ड इनको रखना चाहिए था वह इनअखबार वालों ने नहीं रखा और आज वह अपनी करनी की फिर कर रहे हैं। इसलिए सरकार को नये अंकुश लगाने पड़े। जैसा इन्होंने किया है, वह इनको भोगना चाहिए। आज किसी का अकारण ही चरित्र हनन करने की उन्हें छूट नहीं दी जा सकती है।

हम सन् 1946 से बराबर काम करते चले आ रहे हैं। बड़े-बड़े सम्मेलन आर्गेनाइज किये, यूथ सम्मेलन किये लेकिन इन्होंने कभी उनको पब्लिसिटी नही दी और जो इनके दोस्त रहे हैं, अगर वह दो मिनट के लिये किसी सम्मेलन में भी चले गये तो उनके लिये पूरे कालम के कालम चले आ रहे हैं छपकर।

मंत्रालय ने जो एक बड़ा कदम उठाया है, सैंसरशिप के नये कानून बनाये हैं, इनके लिये मैं दिल से अपने मंत्रालय का आभार प्रकट करता हूं।

हमारे इस मंत्रालय ने अपने टेलीविजन और रेडियो के जरिये जो किसानों का प्रोग्राम रखा है, युवः-वाणी शुरू की है, इससे एक नई भावना लोगों में आ रही है, नई योजनाएं और जानकारी लोग प्राप्त कर रहे हैं। खेती का प्रोग्राम जो किसानों के लिये आता है, उससे इन्सैक्टीसाइड्स, बीज और खेती में तरक्की के बारे में जानकारी दी जाती है। देहात के लोग बड़ी दिलचस्पी से उसको सुनते हैं। जो लोग यह समझते हैं कि किसानों को दिलचस्पी नहीं है, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि हमको पता नहीं लगता है कि इस पार्लियामेंट में क्या कार्यवाही हुई है लेकिन

गांव का साधारण किसान बता देता है कि आपकी पार्लियामेंट मे यह हुआ है।

इस मौके पर मैं एक बात और कहना चाहता हू। महिलाए हमारी प्रतिष्ठा, इज्जत और आदर की पात्र हैं। लेकिन आज जो पब्लिसिटी की जाती है, उसमे स्त्रियो की नगी तस्वीर दी जाती है, चाहे जूते की दुकान का प्रचार हो, बर्तन, दवाई और चाहे लोहे के सामान का प्रचार हो, किसी काम का प्रचार हो हर जगह स्त्रियो को प्रचार का माध्यम बनाया जाता है। इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इस मत्रालय के पब्लिकेशन ने सारे देश मे बहुत अच्छी पुस्तके बच्चो और बडो के लिये छापकर सस्ते दाम पर बिकवाकर अपने देश के इतिहास से बडी जानकारी उपलब्ध कराई है।

मुझे इस बात की खुशी है कि इस मत्रालय की रिपोर्ट मे कहा गया है कि अश्लील प्रकाशनो और फिल्मो मे दिखाई जाने वाली नग्नता तथा सैक्स की भावनाओ को उभाडने की प्रवृत्तियो को कर्ब किया जा रहा है। मैं चाहता हू कि इस दिशा मे ज्यादा मजबूती और तेजी के साथ काम किया जाये। हम देखते हैं कि आज केवल सैक्स और फाइटिंग सम्बन्धी फिल्मे चलती है, जब कि दूसरी फिल्मे नही चल पाती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी फिल्मे सस्कृति, सभ्यता और मनोविज्ञान आदि विषयो पर आधारित हों। इस समय फिल्मो मे जो पश्चिमीकरण के दृश्य और संवाद आदि पाये जाते है, उनको कर्ब करना चाहिए। कई फिल्मो ने हमारे नौजवानो पर ऐसा असर डाला है कि उन्होने डाके डाले हैं, बैंक लूटे हैं और छुरे तथा पिस्तौल चलाये हैं। ऐसे चलचित्रो के बनने पर अकुश लगाया जाना चाहिए।

इन अलफाज के साथ मैं इस मत्रालय को बधाई देते हुए उसकी मागो का समर्थन करता हूं।

SHRI C. T. DHANDAPANI (Dharapuram): Mr. Deputy-Speaker, Sir, following the declaration of Emergency, a new meaning is given to the democratic principles in this country. On the basis of that, many dailies and weeklies belonging to the Opposition parties have been banned in this country Even the historical facts are not being allowed to be published in the newspapers Poems and songs for promoting world culture are also stopped from publication in the papers Enactment of dramas is also not allowed in any part of this country. Things that are allowed in the newspapers are those which are supporting the Government and their policies, which are accusing, in a very bad manner, all the opposition parties alone It has been said much about Samachar organisation The news agencies have been brought under one organisation Before this came into being, there were four news agencies. I want to ask a specific question from the Ministry Whether after the formation of Samachar, the sale of newspapers has increased or reduced? As far as my knowledge goes, the sale of newspapers is considerably reduced because different types of news from various parts of the world have not been published now in the papers. Only one type of news is published in all the papers So, the public have no interest in reading newspapers Previously they used to buy 5, 6 or 8 newspapers to read news of various parts of the world Now, they buy only one paper so that they will have the satisfaction of reading 80 or 100 papers This is the position The Minister, though he is not present here at the moment, is a competent man. But at the same time, I would say that he is more competent and suitable for political work than for a Department like this He is giving more time only to those who accuse the Opposition parties through the media of A I R and TV That is why many things have happened without his knowledge. I want to mention here an instance about the irrational decision taken by the Ministry in regard to the surrendering of the Southern Regional Engineering Office to TV (India) which

[Shri C. T. Dhandapani]

has been established in Delhi. In 1968, the Ministry had established four Regional Engineering Offices, namely, Western Region (Bombay), Eastern Region (Calcutta), Northern Region (Delhi) and Southern Region (Madras). The Southern Regional Engineering Office at Madras represented the States of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Pondicherry and the Andaman Islands. The functions of the Regional Engineering Office are to instal new broadcasting stations, undertaking technical supervision and maintenance of broadcasting stations. The Southern Region has commissioned 8 projects so far. 2 more are to be completed. 14 projects are yet to be taken up in the fourth and fifth plans. The regional office at Madras is directly supervising 23 stations in the region. There are 200 members of the staff in the regional office at Madras of which 132 are Class III and IV staff. The government took the decision to separate TV from AIR. Proposals were sent to the ministry to wind up any one of the four regional offices at Delhi, Calcutta, Bombay and Madras It seems a final decision has been taken by the ministry to wind up the southern regional office and send all those employees to Delhi. The simple reason why they chose to wind up the Madras office is that we in South India do not resist any decision taken by the Centre If we resist it, we will be branded with some other name. Instead of surrendering the southern region and sending all those employees to Delhi; they can make use of the staff in the regional engineering office, AIR, New Delhi, so that no staff member will be affected. Delhi office is already handling TV projects which are to come up and such a wise step would enable smooth transformation. The future TV projects except two are to be installed around Delhi only. In that case, it would be easier for them If you cannot utilise the services of the Delhi office staff, they could be chosen from the four existing regional offices, and by pooling them for forming a regional office for TV in Delhi, instead of winding up the southern office and taking all the members of the staff from Madras to Delhi. In that case, none of the existing offices need be abolished.

There is a sound project with headquarters in Delhi, which can conveniently be entrusted to TV India in Delhi.

They are planning to instal 9 TV stations in the coming years. 7 of them will be around Delhi. 2 will be given to Hyderabad and some other place. I want that Coimbatore, which is an important industrial place, must have a TV station. About having a broadcasting station in Madurai in Tamil Nadu, a proposal has already been sent to the ministry. It seems it is lying here awaiting sanction. The feasibility report has also been sent to the ministry. I request the ministry to sanction this.

For new projects under the Ministry, Rs 10 crores were allotted for the whole country. This estimate was revised and reduced to Rs 5 5 crores. But the funny part of it is that after the revision of the estimate, no amount has been sanctioned to the southern region and this Rs. 5 5 crores is meant only for other regions. This should be looked into.

Many members spoke about censorship. Recently, through AIR a wild and malicious propaganda was let loose, alleging that DMK is secessionist and anti-national.

Suppose certain allegations are made against somebody. The person who is accused, must be given an opportunity to defend himself. That is not being given now. The DMK—headquarters has issued a detailed, explanatory statement saying that the DMK has always stood for national integration, and its unity and sovereignty of this country. Even the 3 or 4 offenders in this respect who were in our party, were expelled from our party; and they were prosecuted against by

the government. Some of the offenders, after they were thrown out of their party, have taken refuge in the Congress. I may mention the name of Mr. Mayathevar. And they have taken refuge under the Congress and the ADMK. The statement which was issued by the DMK with good intentions, has been censored heavily by the Censor; and the important portions denying the charge of secessionism have been omitted. Some dailies in Tamil Nadu have no pre-censorship; but the parties opposing the government—not opposing the government, but opposing the principles of the government—are not being allowed.

I want to quote Mr. Shukla; he has said:

"Press censorship would lapse with the revocation of the Emergency; but the Government wanted to re-structure the Press, so that there was no confrontation in future between the two."

He means the government and the Press. I want to ask the Government specifically, whether they want the entire Press in the country to give blanket support even to the omissions of the Government Will the Government assure the people that they will never do wrong in future? Secondly, the Government may do wrong sometimes in the matter of planning, taxation and other fiscal policies. In such cases, the Government can expect from the Press, concrete and constructive criticism; but when the Government or the party in power at the Centre deliberately indulges in misdeeds for the benefit or survival of the ruling party, do they want the Press to support it also? If the Government expects it, India will not be a democratic country. It cannot be so. We have seen certain European countries where they had controlled the news media. We know what happened. They had become totalitarian countries, not democratic countries. Again, Mr. Shukla had said:

"Before Emergency, some newspapers were indulging in creating an atmosphere of violence, hatred and were carrying on a regular campaign......."

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have exceeded youd time.

SHRI C. T. DHANDAPANI: I will finish in two minutes, Sir. I have always obeyed you. I quote:

"....against constitutionlly-elected legislators' governments at the State and the Centre."

This is a welcome statement. He has also said on 14-11-75 at Bombay:

"The press should be free to fearlessly and constitutionally criticise the policies of the Government; which did not, however, mean indulging in frontal attacks and character assessination, which could pose a danger to constitutional and political stability"

But the Government's media, *viz.* the AIR and the Television are themselves engaging in character assassination.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude

SHRI C T. DHANDAPANI: One minute There is misuse even by AIR at Madras. They invited some political leaders for a talk. They accused the DMK leaders as robbers and thieves. The same words were used in the All India Radio Mr. Sezhiyan wanted the texts of the speeches and the conversations He was told, "we have no text". The misuse of mass media of the Government of India, *viz* the TV and the AIR in Tamil Nadu is well-known. The Central Government has constituted a commission of enquiry to enquire into the so-called allegations against the DMK government. After initiating the judicial process, political parties opposed to the DMK are invited by the AIR in the name of conversation and debates; they then relayed the utterances and character assassinations made by those people against the DMK leaders and workers, through the TV and the AIR.

14.00 hrs.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): Sir, I rise to support the Demands for Grants presented to this House by the Minister for Information and Broadcasting. I take this opportunity to compliment the Minister and his team of officers throughout the country for rising to the occasion and giving wide publicity to the 20-Point Economic Programme, which has energised the whole country.

I learn from the Annual Report presented by the Minister to this House that 34 documentaries have been prepared on this programme. I would request that many more documentaries, and that too in regional languages, should be prepared and sent to the villages so that the people are able to have a feel of this programme from the projectors which the Department is able to send to the villages off and on.

That the Ministry have made rapid progress is clear from the fact that at the end of 1974 there were 15 million radio and 2.76 lakh television receiver licences. I would point out that I had expected that the Ministry's Report would give us the figures at the end of 1975, because the Report under review was for the year 1975-76 But, unfortunately, the Report is one year behind and the figures are given for the year ending 31st December 1974 I think for the future it would be a good thing if figures are given for the previous calender year, so that the country can know what is the total number of licences each year for both radio and TV in the country.

I would like to compliment the Minister for the programmes for University education which are broadcast over the radio. These days the radio and the television are being used the world over for education, where they are found useful. During my visit to Japan I saw that TV was being used in school and college classes for teaching subjects like mathematics and physics.

I find from the Report that 24 stations broadcast programmes for University education in English or regional languages, and they are broadcast three times a week. The Jullundar station broadcasts correspondence courses for the University of Punjab. We in Simla have also the Himachal Pradesh University which conducts programmes for correspondence courses in various subjects. I would suggest that some time be allotted by this station for correspondence course, just as it is being done by Madras, Delhi and Jullundar stations.

My main point of examination is the field publicity work of the department. After the emergency, the people at large have understood the importance of the media of communication and the nation is aware of the important role that the Ministry can play, and the radio and television can play in high-lighting the strides that the nation is making day in and day out. The Prime Minister's broadcast to the nation on the eve of the Independence Day 1975 was, for the first time, sent to 2,400 villages over the SITE. Similarly programmes are broadcast over the SITE for six days a week This is a very happy sign that the country is coming up

But my main demand is that the thrust should be into the interior. We find from the Report that the officers go into the rural areas I would refer to my own State, where the need for field publicity is more important there in many other States, because there are no daily newspapers published from that State. That State is regularly depending for its supply of newspapers on the adjoining States.

Therefore, they do not have much interest in the developmental activities of our State. As a result, we have to depend mostly on field publicity and the radio station at Simla. I take this opportunity of commending the good work done by the Simla station of AIR which was made more powerful five years ago, and I support the demand made by my Chief Minister, Dr. Parmar, for a T.V. station at Simla.

I request the Ministers's to examine how a State with over 50,000 sq. k.m. of terirtory, having 34 lakhs of population, spreading from Dehra Dun on one side to the borders of China and Jammu and Kashmir on the other, can have adequate publicity with six field publicity units. In particular, I would refer to the Dharmsala unit of field publicity which caters to 23 blocks out of 69 blocks Of the six units in the State, the Dharmasala unit has to cater to one-third of the whole State, 16 out of 61. Assembly constituencies and 15 out of 34 lakhs of the population. The Minister may, therefore, be kind enough to have another unit by bifurcating the unit at Dharmasala, so that a more balanced approach can made to the whole problem and a separate region alongwith an Information Centre should be set up for Himachal Pradesh at Hamirpur.

About the 20-point economic programme, I must stress the fact that the villages are getting to know what this programme is, but the Ministry of Information and Broadcasting should have a double channel. As has been rightly stressed in the Report also. It must take to the villages the point of view and the policies and plans and programmes of the Government, and there must be a feed-back from the people, of their difficulties in implementing the programme or their reaction to the implementation of the programme by the Government.

One of my friends from the opposite side, Mr. Bhaura, referred to the fact that the view of the Deputy Commissioner would be accepted in preference to that of the representatives of the people if there, is a difference, even though the latter may be correct. I have to suggest in this connection that the Minister may think of some suitable machinery in which the public representatives, those who represent the people at the national, State and the panchayat or block levels, are associated with the field publicity work and also with the news that is sent out. I agree with Mr. Bhaura that the State Government officers generally take up items that are related to the officers' programmes or Ministers' tours and they generally neglect other programmes This is happening all over the country, and the result is that in the emergency it is being misunderstood that only the voice of the officer whose name appears in the Gazetted list or the Minister in the Government is authentic and not the voice of the people's representatives. The radio stations, the field publicity units and the various other mass media should see to it that the people's point of view is also adequately reflected and adequately channelised to the quarters to which they should be sent, so that there is mutual action and inter-action and not merely unilateral action, so that Government's policies, whether of the State or of the Centre, are properly publicised all over the country. The people's voice will strengthen Government's voice and Government's voice will give courage and hope to the people

The Prime Minister's words and the programme initiated by the T V through SITE have brought new hope to the people as to what can come out of a situation in which a nation is dedicated to the task of discipline and hard work

Much good has been done by press censorship, there is no doubt about it because, as my friend, Shri Hari Singh, pointed out, a cheap kind of propaganda of a personal character, selfishly motivated propaganda was being carried out and people were being starved of news and drained of their resources.

Now there is a regulated programme. But I would say that censorship should not mean censorship of humour also Humour should not be destoryed and, also, aesthetic taste and appreciation should not be killed. I also have some experience in journalism and I found once or twice, while discussing with some literay figures of Delhi, that they are sore over the fact that some of their

[Prof. Narain Chand Parasher]

poems which they wanted to publish were either stopped or were not allowed to be published as a whole, although there was nothing objectionable in them and they had only some humrous touches.

I want to bring one instance to the Minister's notice. When we were bringing out a weekly, we reproduced Mr. Kamalapati Tripathi's article which was already published. But, from that too, a portion was cut out by the Censor and I don't know for which reasons because, to my mind, it contained nothing that was not going to encourage the people or make the people more bold in facing the task so far as the Railways were concerned.

So, I would suggest that we should have a balanced approach. If censorship regulates the news items and it gives them a direction and cuts out filthy things and useless things, it is all right, but humour and aesthetic taste and appreciation should be allowed to grow and should not be subjected to censorship.

With these words, I congratulate the Hon. Minister for the good work that the report reflects and I think that, in the years to come, this will be further strengthened and there will be a new hope and courage for the people of the country.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): Thank you very much for providing me with this opportunity for participating in the Demands of the Ministry of Information and Broadcasting. As all have admitted unanimously, broadcasting is the most effective and powerful medium of mass communication in India: It brings useful information and things of an educative nature to the public. As the hon. Member who spoke before me and several others have admitted, the Government's policies should reach the ears of the villagers. We know that 80 per cent of the Indians ade in villages. So how does this information reach the village level or block level? We are going on propagating so many things, including the effective implementation of the 20-point programme. The people welcome the programme unanimously, but a vast majority of the people are not able to understand the implications of the programme. Due to the abnormal prices of radios and television sets, about 90.9 per cent of the villagers are unable to purchase radios or television sets, and I am extremely sorry to make this comment. The prices of many essential commodities have been reduced considerably and we welcome it with all respect, but what about the prices of TVs and Radios? Their prices should also be reduced We appeal to the Government that they should take immediate steps to reduce the prices of radios, TVs, transistors etc.

Regarding the radios installed in the villages for the poor masses, there are so many radios at the Panchayati level and block level, but we are all aware of the position regarding the functioning of these radios. I have come across so many instances where the radios, although they have been fitted there and have been available for a long time, don't function at all. The radios in the Panchayati offices and block offices are not working. I have myself seen this in so many villages while we were visiting several places. Therefore, the Hon. Minister must see that proper instructions are given to the States and their radio offices to check up whether the radios which have been made available to the villagers at the block level are working or not

What is the use of having the more physical presence of radios without their being in working condition? It is like having a dead body which is of no use to any one. Therefore, the hon. Minister may please look into this matter.

According to the data published by the Government of India, at the time of Independence, there were 2,75,000 radio sets in India. At that time we were having only 35 to 40 crores of people. But now the population has

increased to more than 50 crores of people. The population in India increases in geometrical progression. The number of radio and TV sets should also be raised in proportion to the increase in the population, so that they are used for the effective implementation of our policies and programmes.

There are two sets of newspapers in India, including Tamil Nadu. One set of newspapers have welcomed the 20-point programme, the declaration of Emergency and the President's rule in Tamil Nadu because they are essential and inevitable in the interest of the country, for the safety and security of the country. But there is the other set of newspapers which are controlled by self-interested people, by the vested group, who are not at all loyal to our country; they are, even now, favouring China, Pakistan and USA.

My learned friend, Mr. Dhandapani, while speaking on the Demands on behalf of the DMK Party, said that there were no leaders, supporting the secessionist or separatist views, in the DMK Party. I can say that almost all the Ministers there were supporting American imperialism and some other—isms—beyond nationalism. Those people have not yet been arrested. I am only replying to the point raised by the DMK Member, Shri Dhandapani; otherwise, I would not have talked about it.

As I was saying, there are certain newspapers in Tamil Nadu and elsewhere throughout the country who are, even now, attacking and criticising impliedly or indirectly the 20-point programme. I can give certain names, but I may not be allowed by the Deputy-Speaker It is because of that I am not mentioning the names There are certain papers, particularly in Tamil Nadu, who are attacking the 20-point programme. I wonder how these people are allowed to do so I am shedding tears every day that these newspapers are being allowed to continue to publish these things even now. There are also certain papers which are supporting the 20-point programme and which are working for the effective implementation of the 20-point programme; but these papers are also facing the on-slaught in Tamil Nadu. I am not mentioning the names of the persons who are controlling there because I will not be allowed to mention the names here. I would request the hon. Minister to ensure proper implementation of the policies and programmes through the media of newspapers in Tamil Nadu.

I understand—I am speaking subject to correction by the hon. Minister—that even now secret communication sets are used by our enemies—from our soil—the so-called Rajas. You have arrested some Rajas who have betrayed our country, who did not have the spirit of nationalism. I understand from some reliable police sources that there are still some people who have not been arrested and that such persons are using the radio and other media of communications against our national interest. I would request the hon. Minister to look into this matter in the interest of our country.

With these words, I support the Demands for Grants in respect of the Ministry of Information and Broadcasting.

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने मिनिस्ट्री आफ़ इनफर्मेशन एंड ब्रोडकास्टिंग की बडी तारीफ़ की है, और तारीफ की बातें हैं भी। लेकिन हर एक आदमी का अपना एस्टीमेशन होता है कि अगर आकाशवाणी में कुछ सुधार कर दिये जायें, तो देश का और फ़ायदा हो सकता है। इसलिए मैं जो विचार आपके समक्ष रखूंगा, वे इसी दृष्टिकोण से रखूंगा। कुछ कामों की तारीफ़ तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो कमियां हैं, जो बातें खटकती हैं, उनकी तरफ़ मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

[श्री राजदेव सिंह]

मैं समझता हूं कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा क़बूल करने के बाद आज भी आकाशवाणी पर अंग्रेज़ी का साम्राज्य बना हुआ है और वहां हिन्दी की तरफ़ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जहां तक हिन्दी न्यूज़ बुलिटन का सम्बन्ध है, मैं दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। दो साल पहले की बात है कि एक हिन्दी न्यूज़ बुलिटन में कहा गया कि केरल के प्रधान मंत्री—"मुख्य मंत्री" नहीं, "प्रधान मंत्री"—, श्री अच्युत मेनन ने अमुक-अमुक बात कही। मैं समझता हूं कि एनाउंसर महोदय इतनी लियाकत के थे कि उन्हें प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री में कोई फ़र्क नहीं मालूम होता था।

उन दिनों गल्ला-वसूली की बात चल रही थी। रोज़ यह फ़िगर दी जाती थी कि आज इतना गल्ला वसूल हुआ। हिन्दी न्यूज़ बुलिटेन में कहा गया कि आज इतने हज़ार मन और टन गल्ला वसूल हुआ। शायद एनाउंसर ने मन और टन दोनों को बराबर समझा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हिन्दी के ऐसे एनाउंसर रखे जाते हैं, जिनको मन और टन में कोई फ़र्क नहीं मालूम होता है। मैं समझता हूं कि यही बात काफी है इस बात को साबित करने के लिए कि आकाशवाणी में हिन्दी की उपेक्षा हो रही है।

जहां तक कृषि-दर्शन का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में चूहों से लोग बहुत परेशान हैं। यहां पर हमारे देश की आबादी से तीन चार गुना ज्यादा चूहे हैं। तीन चूहे एक आदमी की खुराक के बराबर अनाज खा जाते हैं। अगर हम चूहों से अपने अनाज को बचा सकें, तो हमें विदेशों से अनाज मंगाने की ज़रूरत न पड़े। लेकिन इस बारे में आकाशवाणी से किसी तरह का प्रचार नहीं किया जाता है। जैसा कि और देशों में किया गया है, गवर्नमेंट को यह घोषणा करनी चाहिए कि जो लोग चूहों को मारेंगे, उनको हर एक चूहे के पीछे एक रुपया या आठ आने दिये जायेंगे। आज गांवों में बहुत से लोग बेकार हैं। यह उपाय करने से साल भर या छः महीने में चूहे हमारे देश में से ख़त्म हो जायेंगे, जिससे लाखों टन गल्ला बचेगा और हमें बाहर से गल्ला मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

जब भी रेडियो या ट्रांसिस्टर खोलें, तो न्यूज़ आइटम के अलावा सिनेमा के गाने सुनने को मिलते हैं। मेरा कहना यह है कि सिनेमा के गाने सुना कर लोगों को ऐयाशी की तरफ़ क्यों ले जा रहे हैं, जिससे उनके दिमाग बेकार हो जायेंगे। क्यों न नैशनल सांग्ज़ सुनाये जायें?

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) केवल राम-भजन होना चाहिए।

श्री राजदेव सिंह : नैशनल सांग्ज़ में सिर्फ़ राम-भजन नहीं है। 1930 और 1932 की मूवमेंट में ऐसे सांग्ज़ गाये जाते थे कि सोता हुआ आदमी जग जाये। ऐसे जोशीले गाने होते थे कि सोते हुए लोग उठ जाते थे और चारपाई पर नहीं पड़े रह सकते थे। ऐसे गानों से देश में एक नैशनल कैरेक्टर बनेगा।

मैं ने अभी हिन्दी की उपेक्षा का ज़िक्र किया है। मंत्रालय की रिपोर्ट के पेज 122 पर प्रैस इनफ़र्मेशन ब्यूरो की पब्लिसिटी रिलीज़िज़ का ब्योरा दिया गया है। 1975 में अप्रैल से दिसम्बर तक उन्होंने अंग्रेज़ी में 11,529 पब्लिसिटी रिलीज़ निकाले, जबकि हिन्दी में केवल 6,336। हिन्दी राष्ट्रभाषा होते हुए भी जितना उधर ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया गया है।

दूसरे, आज भी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं या जो नई संतानें पैदा हो रही हैं उन्हें हमारे लिबरेशन मूवमेंट के बारे में, आज़ादी के आन्दोलन के बारे में बहुत कम जानकारी

है। इसलिए समय-समय पर एथारिटेटिव रूप से आकाशवाणी पर मूवमेंट का पूरा विस्तारपूर्वक वर्णन आना चाहिए। यह आजादी का मूवमेंट 1857 से लेकर 1947 तक स्टोरीज मे और ड्रामा वगैरह मे दिखाया जाना चाहिए ताकि लोग उसे समझ सके।

ट्रासमिटर हमारे उतने मजबूत नही हैं जितने होने चाहिए। पेकिंग की आवाज भी यहा बहुत साफ सुन लेते है, मास्को भी सुन लेते है, बी बी सी भी सुन लेते है लेकिन हमारी अपनी आवाज कभी-कभी दूर सुनने मे बडी मुश्किल पड जाती है। तो ट्रासमिटर थोडे और मजबूत किये जायें।

अब थोडा फिल्म और फिल्म सेंसरशिप के बारे मे कहना चाहता हू। फिल्म अगर एजूकेटिव हो तो बडा अच्छा है और फिल्म सेंसर बोर्ड मे भी ऐसे लोग रखे जायें जो सोशल थिंकिग के हो और पोलिटिकल आउटलुक जिनका क्लीअर हो कि किस तरफ हमे समाज को ले जाना है। एक पिक्चर भी आई थी थोडे दिन पहले पाकेटमार। यकीन मानिये जिन जिन शहरो मे वह दिखाई गई होगी वहा दर्जनो पाकेटमार उसने बनाये होगे। जो पिक्चर्स आज चलती है अपने टोले मुहल्ले मे या गावो मे लोग लडकियो को फसाने और भगाने मे उनको इस्तेमाल करते है जैसे कि सिनेमा मे देखते है कि आख मिली नही कि मुहब्बत हो गई। इस तरह की जो पिक्चर्स है इससे हमारे नौजवानो पर बडा बुरा असर हो रहा है। ये पिक्चर्स क्रिमिनल्स पैदा कर रही है।

श्री भगवत झा आजाद इसका असर बूढो पर भी पडता है, केवल बच्चो पर ही नहीं।

श्री राजदेव सिंह दूसरी चीज मैं कहना चाहता हू पब्लिसिटी के बारे मे। टूरिस्ट हमारे देश मे ज्यादा आयें इसके लिए चाहे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या और कोई पब्लिक प्लेस हो सभी जगह हमारे देश की काली औरतें दिखाई जाती हैं जिनके बदन पर अच्छी तरह से कपडे भी नही रहते हैं। मैं यह कहता हू कि मिस मेयो यहा आई थी और मदर इंडिया उसने लिखी थी। लालालजपत राय ने फादर इडिया लिख कर उसका जवाब दिया और उन्होने कहा था कि मिस मेयो हमारे देश मे गटर्स इसपेक्टर हो कर आई थी। उसने यहां की नालियो को सूघा, यहां के गुलाब के फूलो को नही देखा। हम जानते है कि हमारे देश मे काले भी हैं। गोरे भी हैं। खूबसूरती की कमी नही है। तो टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम हाफ-स्टार्व्ड काली औरतो को दिखाए जिनके बदन पर पूरा कपडा भी न हो—और अभी जो पार्लियामेट का नया एनेक्सी बना है उसमे भी इस तरह की फोटो आपको देखने को मिलेगी—तो यह कोई अच्छ प्रचार का बहाना नही है। अच्छी शक्लें दिखाई जा सकती थी जैसी आपके देश मे है और इससे मैं समझता हू कि टूरिस्ट्स पर कोई बुरा असर नही पडता

टेलीविजन के बारे मे थोडा सा यह कह देना चाहता हू कि जैसे अब टेलीविजन का लखनऊ का सेंटर खुलने वाला था तो लखनऊ के सेंटर के लिए कौन से वर्कर्स होंगे उनके सेलेक्शन दिल्ली मे किया गया था। मैं समझता हू जिस एरिया मे जो सेंटर हो वहा के वर्कर टेलीविजन के उसी एरिया के हों तो वे ज्यादा वहा की चीजो को समझ सकते हैं और उसे डेपिक्ट कर सकते हैं। थोडे दिन पहले यह भी बात आई थी कि टावर थोडा ऊचा कर दिया जाय तो लखनऊ टेलीविजन को बनारस और इलाहाबाद के लोग भी देख सकते हैं, नही तो केवल कानपुर तक वह सीमित रह जाता है। एक स्टोरी दो स्टोरी और ऊचा कर दिया जाय तो वह कैच कर सकता है अभी साइट का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अलावा। साइट का जो 24 सौ गावों मे चल रहा है वह तो चल ही रहा है लेकिन वह मुस्तकिल होगा या नही यह नहीं कहा जा

[श्री राजदेव सिंह]

सकता । शायद अमेरिका वाले बिदड़ा कर लेंगे महीने दो महीने बाद । अगर यह हो जाय तो यह एक एक्सपेरिमेंट है लेकिन बड़ा अच्छा है ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय का परिवार ऐसा रहा है जो कि आजादी की लडाई में बहुत अग्रणी रहा है, बडा अगुवा रहा है और मैं जानता हू आपको देश के प्रति दर्द है । आप चाहते हैं कि देश बढे, तरक्की करे । इसके लिए जैसे कि हमारे बहुत से साथियों ने निन्दा की न्यूज एजेंसीज की तो आप ने सब को तोड कर एक एजेंसी बना दी । यह बडा अच्छा काम हुआ । यहा बहुत सी बाते की गइ प्रेस की आजादी और एक्सप्रेशन की तो मैं कहना चाहता हू कि मुझे छड़ी घुमाने की आजादी है लेकिन छडी घुमाते हुए अगर किसी की नाक को चोट पहुचायेंग तो वही हमारी आजादी खत्म हो जाती है । हरएक आदमी को फ्रीडम है एक्सप्रेस करने की, लिखने की लेकिन जब वह देश के लिए नुकसान पहुचाने लगता है, देश को कमजोर करने लगता है, देश ने जो डेमोक्रेटिक सेट अप स्वीकार किया है उसके खिलाफ वह चलने लगता है और सेक्युलरिज्म के खिलाफ चलने लगता है तो उसको वहीं रोक देना चाहिए ।

मुझे थोड़ा सा न्यजपेपर्स के बारे मे भी कहना है । बडे बडे सर्क्युलेशन वाले जो बड़े-बडे न्यूज पेपर्स हैं वह ज्यादातर कैप्टेलिस्ट्स के हैं । सिर्फ नेशनल हेराल्ड और पैट्रियाट या कुछ प्राविंशियल पेपर्स हैं जो बडे आदमियों के नही हैं । ऐसी हालत मे इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि पूंजीपति देश की पर्वाह नहीं करते हैं, अगर अफ्रीका में कोई प्लांट लगाने से फायदा है तो वे देश के लोगों की फिक्र नहीं करेंगे । दूसरी तरफ जो छोटे-छोटे अखबार हैं, प्राविंशियल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेविल के वह बड़ा अच्छा काम करते हैं । वह अखबार कैप्टेलिस्ट्स के नहीं हैं बल्कि साधारण लोगों के हैं या कोआपरेटिव बेसिस पर जो आर्गनाइजेशन्स हैं उनके हैं । इन अखबारों को एडवर्टीजमेन्ट्स देने चाहिए और हर तरह से एन्करेज करना चाहिए । इसी तरह से न्यूज पेपर्स का जो रजिस्ट्रेशन होता है, महात्मा गांधी को डिक्टेटर कहने वाला न्यूजपेपर भी रजिस्टर्ड है इस देश में । तो रजिस्ट्रेशन का कोई मापदण्ड होना चाहिए, कोई शपथनामा उनसे लेना चाहिए कि देश के एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के खिलाफ कभी नहीं जायेंगे । इसके बाद ही उनको प्रकाशन की इजाजत देनी चाहिए । मैं समझता हू मंत्री महोदय इसकी तरफ ध्यान देंगे । इसके अलावा जैसा मैंने कहा इस मंत्रालय पर अंग्रेजी छाई हुई है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए । हिन्दी को जितना मजबूत होना चाहिए वह नही है । इसलिए हिन्दी को मजबूत करने का भी प्रयत्न करें । इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष जी, मैं सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि शुक्ला जी, आप और आपके मन्त्रालय को मैं धन्य कहता हू लेकिन आपने इतनी देर के बाद यह कदम क्यों उठाया, पहले ही क्यों नही यह कदम उठाया जबकि ऐसे तत्व हमारे देश में विद्यमान थे जोकि समाचारपत्रों के माध्यम से इस प्रकार का अनर्गल प्रचार करते थे, प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर जो लोग स्वच्छंदता का अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे और उसका इस तरह से दुरुपयोग करते रहते थे इस देश मे और इस देश के बाहर कि जिससे इस देश की इमेज खराब हो, देश के राष्ट्रीय नेताओं का चरित्रहनन हो, जनता का मनोबल गिरे और जिस तरह से अमरीकी एजेन्टों ने क्यूबा और चिली में घृणित कार्य किये उसी स्थिति को हमारा देश भी पहुंच जाये और एक बार यह देश फिर कमजोर और गुलाम बन जाये। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर

आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश में आजादी की लड़ाई के दिनों में अखबारों की कुछ मान्यतायें थी लेकिन आजादी की लड़ाई के बाद कुछ अखबारों की मान्यतायें बदल गईं, वह जो इजारेदार पूंजीपति थे उनके हाथों में चले गये और कुछ जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स थे उनका उनपर आधिपत्य हो गया या जो इलाकावाद और फिरकापरस्ती की भावना पैदा करने वाले स्वार्थी तत्व थे उनके हाथों में कुछ अखबार चले गये और फिर उन्होंने उनका इस्तेमाल अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए किया।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हू कि आपात्-कालीन स्थिति की जो घोषणा हुई उससे लगभग दो महीना पहले, इसी सदन के एक माननीय सदस्य है, जनसघ के बहुत बड़े शीर्षस्थ नेता है जिन्होंने हैदराबाद मे एक प्रेस वक्तव्य मे कहा था कि विचारों की जो हमें स्वतत्रता है उसके नाते आम जनता को रेडियो चलाने की आजादी होनी चाहिए। वहीं पर उसी प्रेस वक्तव्य मे जोकि अखबारो में छपा था, उन्होंने कहा था कि हम आल इंडिया रेडियो के प्रसारण को जॅम करने की योजना बना रहे है और उस अवसर की तलाश मे है। अखबारों ने इस बात को पब्लिसिटी दी। उसके बाद इमर्जेन्सी लगी और उसके बाद कुछ स्थानों पर जो हाई पावर ट्रांसमीटर्स पकड़े गये वह इस बात के तथ्य है कि उनकी इस देश मे कितनी बडी साजिश थी, किस प्रकार वे देश को गुमराह करना चाहते थे और किस प्रकार देश मे गलत प्रचार करना चाहते थे। पिछले कुछ वर्षों से, जब से प्रधान मंत्री जी ने देश के सर्वहारा, कमजोर और पददलित वर्गों के उत्थान के लिए कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स के स्वार्थों पर प्रहार किया, कुछ कार्यक्रम बनाये, कुछ कानूनों में परिवर्तन किये तब से यह सारे स्वार्थी वर्ग और उनके इशारों पर चलने वाले समाचार पत्रों ने चारों तरफ से प्रधान मंत्री को टार्गेट बनाकर प्रहार करना शुरू कर दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि देश की जनता का मनोबल गिरने लगा।

पिछली बार राष्ट्रपति जी का जो चुनाव हुआ, 1965 में जब डा० जाकिर हुसैन साहब उपराष्ट्रपति थे और भारत-पाक युद्ध हुआ, उस समय कितना गलत और भयानक प्रचार कुछ समाचार-पत्रों के माध्यम से किया गया। आज जब उसकी कल्पना करते हैं तो आश्चर्य होता है कि हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन समाचार पत्रों के विरुद्ध उस समय कार्यवाही क्यों नही की। इस लिये मैं समझता हू कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद प्री-सेन्सरशिप के द्वारा इस प्रकार के तत्वों पर जो प्रतिबन्ध लगे हैं—वे उचित हैं और सारे देश ने उनका स्वागत किया है और यह भी खुशी की बात है कि पिछले अगस्त से आपके मत्रालय ने प्री-सेन्सरशिप को हटा दिया है, अब बहुत कुछ समाचार-पत्रों के विवेक पर निर्भर करेगा कि वे किस प्रकार से देश के रचनात्मक कार्यों के समाचार दे। प्रेस पर अनुशासन लाने के लिये पिछले दिनों आपके मत्रालय ने जो "प्रीवेन्शन आफ पब्लि-केशन आफ आब्जैक्शनेबल मैटर बिल" इस ससद् से पास करवाया—यह भी एक बहुत अच्छा कदम था। इसका श्रेय न केवल आपके मत्रालय को जाता है, बल्कि देश के शीर्षस्थ 17 समाचार-पत्रों के सम्पादकों की उस कमेटी को भी जाता है, जिसने कोड आफ कन्डक्ट के रूप मे अपनी रिपोर्ट शासन के पास भेजी थी, जिसे इस सदन मे भी प्रस्तुत किया गया था।

हमारे सोम नाथ चैटर्जी साहब ने अभी अपने भाषण मे कहा था कि आप उन पत्रकारों के नाम दीजिये तथा उनकी कार्यवाहियां बतलाइये, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। वे अमरीकी प्रेस स्वतत्रता और इंग्लैंड की प्रेस स्वतंत्रता की बहुत ज्यादा बात करते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि

[श्री हरिकृष्णसिंह चैन्सूली]

अमरीका और इंग्लैंड के प्रेस नें भले ही निक्सन के खिलाफ़ बातें की हो, सी०आई०ए० के विरुद्ध छापा हो, लेकिन जहां तक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध है, वहां के समाचार पत्रों ने और खास कर वे सम्वाददाता जो हिन्दुस्तान में रहते थे, उन्होने अपने देश की नीति और कानून के अनुसार काम किया, जिस का भण्डाफोड़ पिछले दिनों हुआ। उनमें कई संवाददाता ऐसे थे जो सी० आइ० ए० के पैसे के आधार पर हमारे देश में काम करते थे, इसी लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई। मैं इसी सन्दर्भ में आपके सामने "हचिन्ज कमीशन" की रिपोर्ट के एक अंश को उद्धृत करना चाहता हू—

"The moral right of free public expression is not unconditional. Since the claim of the right is based on the duty of a man to the common good and to his thought, the ground of claim disappears when this duty is ignored or rejected"

इसी कमीशन की रिपोर्ट के एक अन्य स्थान पर लिखा है—

"The freedom of the Press does not mean that the general laws of the country should be inapplicable to them. The freedom of the Press also does not mean that special laws should not be there to govern certain types of utterances"

मान्यवर, इस प्रकार अमरीका मे भी इसकी व्यवस्था है, दूसरे देशो मे भी व्यवस्था है और हिन्दुस्तान मे ही नही, हमारे पडौसी देश सीलोन और नेपाल मे भी इस प्रकार के समाचार पत्रो के अनर्गल प्रचार पर प्रतिबन्ध लगा है। मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय ने जो नया कानून बनवाया है, जब पूंजीपतियो के चंगुल से समाचारपत्र निकल जायेंगे और निहित स्वार्थ वाले वर्गों का उन पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा, समाचार पत्रों के सम्पादकों और श्रमजीवी पत्रकारों की सलाह से आप कोई व्यवस्था करेंगे तो इसके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। हमें इस बात का प्रयत्न करना होगा कि हमारे सम्पादकों और संवाददाताओं को किसी प्रकार की घुटन महसूस न हो, उनको ऐसा महसूस न हो कि उनकी आजादी छीन ली गई है। मुझे मालूम है—बम्बई में पिछले दिनों हमारे शुक्ला जी ने प्रेस गिल्ड को सम्बोधित करते हुए कहा था कि हम प्रेस को स्वतंत्र देखना चाहते हैं, हम अंकुश नही रखना चाहते हैं, जल्दी ही दूसरे अंकुश भी उन पर से हटते हुए देखना चाहते है। मान्यवर, मैं आशा करता हू कि जो कानून आपने बनाया है, इससे ईमानदार श्रमजीवी पत्रकारों को किसी प्रकार का भय नही होगा और आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे जिससे समाचार-पत्र और संवाददाता करेंगे कि देश के प्रति उनके कर्तव्य क्या हैं, देश के उत्थान में वे किस प्रकार सहयोग दे सकते है।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हू—कुछ विदेशी पत्रो ने, जिन्होने हमारे देश को उपलब्धियों और हमारे अच्छे काम को तारीफ नही की है, बल्कि आलोचना की है और दूसरे देशों के सामने एक गलत तस्वीर पेश की है—उनके विरुद्ध जो कार्यवाही की गई है मैं उसकी सराहना करता हू। "न्यूयार्क टाइम्ज" ने 22 जुलाई, 1975 को लिखा था—

Democracy had been butchered in India

उसी प्रकार "न्यूज वीक" ने 4 अगस्त को लिखा था कि—

Democracy had been putchered in India.

मैं समझता हू कि श्री सोम नाथ चटर्जी को या तो ज्ञान नहीं है, और अगर ज्ञान है तो जानबूझ कर हिन्दुस्तान के दुश्मनों की तारीफ करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी इस तरह की आलोचना की है, और आप ने

जिनके लिये कार्यवाही की है मैं इसके लिये आपको बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, यही कारण था कि 27 अगस्त के अंक मे "नार्जियन" के एशिया के मुख्य सम्पादक ने इस बात को स्वीकार किया है। और उन्होने अपने अखबार मे लिखा है

> "The Western Press has often been shallow and inaccurate on the bad news"

इसलिए मैं समझता हू कि शासन ने इस सम्बन्ध मे जो कार्यवाही की है वह उचित है और उसकी मैं तारीफ करता हू।

आपातकालीन स्थिति मे दूसरे मत्रालयो ने जिस प्रकार कुछ नये कदम उठाए है और नई योजनायें तैयार की हैं उसी प्रकार इस मंत्रालय ने आपातकालीन स्थिति के बाद सब से महत्वपूर्ण काम यह किया है कि चार न्यूज एजेन्सियो को मिला कर एक "समाचार एजेन्सी" का नाम दिया। यह एक अच्छा कदम है। पिछले दिनो यू०एन०एस०को० की मास मीडिया नामक पत्रिका छपी थी उसमे लिखा था कि 90 देशो मे राष्ट्रीय एजेन्सिया हैं किन्तु 5 एजेन्सिया ऐसी हैं जिनका कि सारे देशो पर आधिपत्य हैं और अपने ढग से बाहर के समाचार उन देशो मे तोड-मरोड कर भेजती हैं और उन देशो के अन्दर के विकास सम्बन्धी समाचार बाहर नही भेजते है। आप ने जो इस ओर कदम उठाया है इससे न केवल आप अपने यहा समाचार की व्यवस्था मे सुधार करेंगे बल्कि दूसरे देशो के साथ समाचारो का आदान-प्रदान करके, उनके रेडियो और टी०वी० तथा समाचारो के साथ हमारा तालमेल बैठायेंगे। इससे स्वस्थ पत्रकारिता को बल मिलेगा।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे मे कुछ कहना चाहता हू। मैं उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र से आता हू। वहा पर आल के आल इंडिया रेडियो प्रसारण का काम सन्तोषजनक नही है। लखनऊ के प्रादेशिक समाचार हम को सुनाई नही देते हैं। इसलिये मेरी माग है कि पर्वतीय क्षेत्र मे, खासतौर से सीमान्त क्षेत्र मे हाई पावर ट्रासमिटर्स लगायें ताकि भारत सरकार के जितने भी प्रचार के काम हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम हैं, उनका प्रचार उन पर्वतीय क्षेत्रों मे खास तौर और भली प्रकार हो सके।

इसी तरह से पी०टी०आई० 26 साल से और यू०एन०आई० 15 साल से हमारे देश मे है। मेरा यू०पी०आई० के साथ सम्बन्ध रहा है। मुझे शिकायत है कि इन्होंने कभी भी हिन्दी को प्रोत्साहन नही दिया। मैं आशा करता हू कि समाचार के माध्यम से आप इनको प्रोत्साहन देंगे।

और अन्त मे श्रमजीवी पत्रकारो के सम्बन्ध मे और आल इडिया रेडियो के जो स्टाफ आर्टिस्ट है उनके वेतन के सम्बन्ध मे निवेदन करना चाहता हू कि उनकी वेतन वृद्धि का प्रश्न आपके सामने है, वह उनको मिलना चाहिए। और पी०टी०आई० तथा यू०एन० आई० के जो मुफस्सिल करास्पोंडेंट हैं जो जिला स्तर पर काम करते है उनको आप नही हटायेंगे और छोटे समाचार-पत्रो की स्थिति को सुधारने के लिये भी आप कदम उठायेंगे और दूसरी ओर यह भी देखेंगे कि छोटे समाचार-पत्रो के नाम पर पैलो प्रेस जिस तरह काम करता रहा है वैसा वह आगे काम न करे। क्योंकि जिला स्तर पर हमे मालूम है कि छोटे छोटे समाचार-पत्र इस तरह का काम करते रहे हैं।

SHRI P G MAVALANKAR: (Ahmedabad) Mr Deputy Speaker, Sir, I am glad to be able to get this opportunity of speaking on the Demands for Grants of a Ministry which, seemingly or apparently, is of a minor status, the Minister not being a member of the cabinet, and from that point of view also, it is of a minor status obviously, but in reality, it is a very vital department of any government, especially, in modern times.

[Shri P. G. Mavalankar]

Now, when you see that a Ministry has got certain asignments and duties which have a relevance to the people's aspirations and difficulties, they should be brought to the notice of the Government and Government's problems and challenges, should in turn be brought back to the people. This area of work, of communication, is all the more important in any modern and democratic or even non-democratic polity and, therefore, from that point of view, I welcome this opportunity of participating briefly in this debate on an important Ministry's demands for grants.

Sir, speaking about Shri Vidya Charan Shukla, I must say that I like him and I have affection for him. But, that does not mean that I like what all he is doing or saying, particularly during the last ten months or so! Sir, he has been coming to Gujarat, and move especially to my home city of Armedabad, quite often—of course, he is in charge of his own party matters and politics and is looking after the people of his party in Gujarat—and, therefore, his visits there are more frequent, but there are no areas of agreement or communication between us, especially, since the declaration of emergency, and I must tell him and the House in all honesty and sincerity that I, as a person, believing in democracy and in freedom of opinion, feel extremely pained at the way things are allowed to deteriorate in the name of democracy I can understand if a country or, the Government of the country says 'we do not believe, temporarily, in democracy: we want to go ahead with the rapid economic progress and, therefore, in a democracy, freedom of opinion etc. may be kept in a refrigerator or in a cool place for some time'—I can understand that argument.

I may not accept it, but I can understand it. But to advance an argument in the name of democracy and discipline that people must conform to one pattern, one ideology and one leader is something which I am not able to digest, believing as I do in freedom of choice and in democracy. The role of the Ministry of Information and Broadcasting in a democracy is crucial, but in a dictatorship also, curiously enough, it is equally vital. In a democracy the Ministry's work is important in as much as it brings the Government's problems and activities to the people and people's aspirations and problems to the Government; but in dictatorship, what it does is that it twists and perverts the vast agencies and instruments of propaganda, of publicity, of information, of advertisement, and thereby it tries to buy the public opinion by brain-washing the people! All that is done in various types of dictatorships. I am sure, my friend, Shri Vidya Charan Shukla and his colleagues do not want the latter thing to happen in the name of democracy in our country. After all, India is an ancient land with rich traditions, and the traditions although in the beginning were Hindu traditions yet by now they have become Indian traditions, of tolerance, of understanding of goodwill. Now, do you expect understanding and goodwill to come through conformism or do you expect them to come through dissent and expressions of different opinions? Therefore, I beg of you to consider again and again whether what you have been doing all along in the recent months is good and proper; Sir, when he says in the Report that he is doing so many things, he may be correct It is perhaps alright from the point of view of economic programme of the Prime Minister that he is doing a wonderful job. Let him be happy about it. Let the country feel happy about it. I am also happy if people living in bungalows and palaces in the big cities feel conscious of the vast number of people, teeming millions of India, who are living permanently almost below the poverty line, and if the well-to-do few feel that they must do something for these millions. If this consciousness is aroused through radio, television, news and features broadcasting publications, literature and pamphlets I am with him on that point. But the point is, does it all require different

points of view to be completely eliminated from radio, newspapers and television? This is the telling question which I would like to address to my dear and esteemed friend. Therefore, I say that although this Ministry's facets of functioning are many—and I must say of absorbing interest to me—yet for a person like me who is both a professor and also a journalist in his own right by writing in various journals in Gujarati, Marathi, Hindi and English, freedom of expression is absolutely essential. I can tell him that it is only through freedom that a full doze of creativity can be obtained. I want to ask Mr. Shukla and this hon'ble House, can creativity come by command performance? Can creativity be a result of an ordered situation in life? Can you have conformism of all opinions into one pattern, one strait-jacket and then order people to love the motherland and do the work for the country's teeming millions?

Sir, if people have different ideas about betterment of people, should those different ideas not be encouraged? I am not saying merely permitted but encouraged to be experssed on the All India Radio, on the Television, through the newspapers, through the advertisements, through articles in magazines, periodicals, books and what not?

Of course, my friend, the Minister, may say that all these restrictions and censorship are only temporary; meaning as long as there is emergency! Then, my question to him would be: How long will you have emergency? If you make emergency a normalcy then even the gains of emergency, whatever they are, will be destroyed. I do not want Indian people to become slaves and fearful of authority. That is not what Gandhiji taught us. Certainly that is not the Indian tradition which teaches us. Indeed, it teaches us to be 'निर्भय' and to be fearless. Fearless of what! Fearless of doing good things, and fearful of doing bad things. You must be पाप भीरु; you must be afraid of committing a sin but you must not be afraid of telling the truth! If telling the truth is a sin according to the Minister of Information and the present Government, then I am sorry for him and for the present Government.

I have no time to go into the details of this Report, but on the very first page of the Report a very interesting sentence appeals which only I would quote. It says:

> "These media units"—AIR, TV etc.—"are the channels for keeping the people all over the country informed about Government's policies, plans and programmes".

So far so good. That you are doing well, more than well, I should say, more vigorously than you ought to. But look at the next sentence.

> "They"—meaning the various media units—"also keep Government informed of public reactions to its policies and activities and provide liaison with State Governments ."

I ask in all humility: how do you get public reaction when you have not allowed the public to react freely and creatively on radio and through the newspapers by your imposing censorship and by all kinds of your party propaganda?

Talking about the emergency, I do not want to take the time of the House by repeating my arguments against it. But I will tell you very frankly that since the declaration of the emergency what I see is an all-round galloping deterioration in regard to an interesting variety of news, comments, and opinions; and, where is the freedom of expression of various points of view so that people can come to their own independent opinions after listening to all these points of view? Can we say that the All India Radio has retained its credibility? I am afraid, it has become more or less an instrument of party propaganda, it has become totally the mouthpiece of the Government.

[Shri P. G. Mavalankar]

I will give an example. Even in the 'Pradeshik Samachar'—I sometime listened to it with great interest—I find that out of 5 minutes of regional news, 4 minutes are devoted to the Congress Party, telling the listeners as to who joined the party and at what time and why! The whole country may join your party. But that does not solve the problems of the Indian people. The problems of the Indian people will not be solved if all of us join the Congress Party or X Party or Y Party. The pdoblems of the Indian people will be solved when all of us, irrespective of party and Independence, whoever they are, sincerely and dedicatedly involve ourselves in the task of nation-building. That is what we want.

I would, therefore, tell the Minister in all earnestness: let not news become dull, deformed and dangerously damaged Let there be variety of choice and freedom on the radio and TV.

Lastly I will touch on two points very quickly. One is about party propaganda. I find that he is using the radio and TV for party propaganda. Up to a point, that can be pardoned, though not justified. But I want to ask him: Can you make AIR and TV exclusively as a reservoir, a property of the Congress Party, and that too of one leader, and not only stopping at that, but of building up another? Is that very good, is that very honourable, is that very sound and very healthy for the development of democracy in our country? The younger generation, boys and girls, are growing in colleges and universities. Do they not want to row in freedom? We who were under dependent India as students of colleges and universities, grew under Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Maulana Azad, Babu Rajendra Prasad and Sardar Vallabhbhai Patel as fearless young individuals Do you want our younger generation, your and my boys and girls, not to grow in a similar atmosphere? Indeed I would say, they should grow in a better atmosphere because we have now got freedom.

While concluding, I would say this: Please make a distinction. My Congress friends are saying again and again—licence, licence, licence! Of course, licence is bad, liberty is good. If then licence is bad and liberty is good, please do not forget this: in order to curb licence, please do not eliminate liberty altogether. That is the only request I make.

I have no time to go into various aspects of the work of the Publications, Song and Drama Divisions etc. They are doing some good work, but much more can be done. Similarly, the *Yuv Vani* is also doing some good work, but here again much more can be done. I will restrict myself just by mentioning this and will pursue it with the Minister through correspondence and by having conversations with him. But I wanted to take advantage of this debate, with your kind permission, Mr. Deputy Speaker, only to say this to him: Please do not use these media, which are so vital for freedom for growth, for health and for productivity in this country, for something which is a short-term, very impermanent and temporary measure, the ends of your party, of your leader and of your would-be leader!

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की मांगों के खिलाफ जो बातें कही गई हैं उनमें मुख्य बात यह कही जा रही है कि प्रेस में विपक्षी दलों की बात नहीं आ पाती है, रेडियो पर उनकी बात नहीं आ पाती है, उनकी चर्चाएं नहीं हो पाती हैं और उन पर सेंसर लगा हुआ है। एक पत्र ओपिनियन नाम का निकलता है जो मासिक है। मुझे याद है यह पत्र करीब करीब हर संसद् सदस्य के पास भेजा जाता था। माननीय सदस्य उसको पढ़ते भी होंगे।

मैं, 30 मार्च की जो पर्चा प्रकाशित हुआ है, उसकी कुछ पंक्तियां आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

> "What has happened during the past nine months has convinced us that the Government has been deliberately destroying our democratic structure brick by brick and now has established an authoritarian regime which it wants to perpetuate"

यदि वास्तव मे इस देश से प्री-सैंसरशिप सख्ती के साथ चल रही होती, तो इस प्रकार के विचार शायद छापना सम्भव न होता। तमाम बातें स प्रकार की निकलती हैं, लेकिन इसके लेखक, और सम्पादक इतने बौद्धिक रूप से चतुर हैं कि वे घृणा का वातावरण बनाते हुए भी अपने विचारो को ऐसे शब्दों मे रखते हैं, जिससे सैंसरशिप का आक्रमण उनके ऊपर न हो सके।

यह बात भी कही गई है कि हाईकोर्टस के जो निर्णय हुए हैं, फैसले हुए हैं उनको भी छापने नही दिया जाता है। जब कोई न्यायालय निर्णय देता है,तो उसमे कुछ तथ्य तथाकथित होते हैं, उसके बाद प्रमाण होता है और प्रमाण के बाद जज का अपना विचार और निर्णय होना है। सैंसर का मतलब ही यह है कि हिंसा, साम्प्रदायिकता बढाने वाले और देश की स्थिरता को भग करने व ले जो विचार हैं, उनको प्रकाशित न करने दिया जाये। अगर न्यायालय के निर्णय मे दिये गये उन्ही तथ्यो को प्रकाशित करने दिया जायेगा तो सैंसरशिप का मतलब ही खत्म हो जायेगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि देश की न्यायपीठ के वरिष्ठ निर्णायक अगर कोई अपना मत व्यक्त करते हैं, अगर उन पर भी सेसर लगा दिया गया तो देश मे जनतन्त्र के चलने मे प्रगति हो सकती है, सफलता मिल सकती है कि नहीं ? इसके बारे में मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे उनका प्रकाशन पर्चों और अखबारों के माध्यम से तब तक न करने दिया जाये जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात् सुप्रीम कोर्ट का अन्तिम निर्णय उन पर न हो जाये, लेकिन ऐसे फैसलों की कुछ प्रतिलिपियां ससद् के पुस्तकालय मे रखी जायें जिससे कि सदन के सदस्य उसको पढ़ सकें, देख सकें, क्योंकि ससद्-सदस्यो को उन जज साहेबान के बारे में अपनी राय कायम करनी होती है कि इस आपातकालीन स्थिति मे हमारी ससद् के बनाये हुए कानूनो पर वह किस तरह व्याख्या करते हैं किस तरह से परिपालन करते हैं। वहा यह जान बूझ कर अपने पद और अवसर का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं जिससे देश की अखडता, स्थिरता और ससदीय प्रणाली में उनके द्वारा स्थिरता पैदा होती है। जजमेंट से उनकी क्या प्रतिछाया पडती है, इसको भी देखना चाहिये।

यह भी कहा गया है कि छोटे छोटे जो पेपर हैं, उनको भी सहायता दी जानी चाहिये। भूमि वितरण का आन्दोलन चलता है कि हर आदमी को भूमि मिलनी चाहिये, मकान मिलना चाहिये, यह बात तो समझ मे आती है, लेकिन अखबार हर आदमी चलाये, छोटे और बडे हरेक पेपर को सहायता दी जाये, इसके पक्ष मे मैं नही हू। इसका कारण यह है कि हर जिले मे, हर इलाके मे जिनके पास पूजी नही है, वह महज ब्लैक-मेलिंग करने के लिये अखबार छाप देते है।

जैसा कि श्री हरीसिंह जी ने कहा कि वे क्या करते हैं अगर कोई ससद्-सदस्य या विधान-सभा का सदस्य उनके पक्ष नही है, तो उसके चरित्र-हनन का समाचार छाप देते हैं। कलैक्टर ने अगर परमिट नही दिया, लाइसेंस नही दिया या रिश्तेदारो के मुकदमे में कोई तरफदारी नही की तो उसके खिलाफ प्रचार कर देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे पेपर जिनका कोई स्टैण्डर्ड नही है जिनकी आचार-सहिता नहीं है, इनको कतई कोई मदद नहीं देनी चाहिये। आखिर एडवरटाइजमेंट किस पत्र

[श्री बी० आर० शुक्ल]

को दिया जाता है ?—जिसका सर्कुलेशन ज्यादा हो । अगर पब्लिक सर्विस कमीशन कलकत्ता की किसी नौकरी का एडवरटाइजमेंट निकालता है, और वह किसी क्षेत्रीय अखबार में, जैसे गोरखपुर में छपने वाले किसी दो पन्ने के अखबार में, प्रकाशित किया जाता है, तो लोग उसको कैसे देख पायेंगे ?

15.00 hrs

हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था मे जो अखबार चल रहे है वे पूंजीपतियो के हाथ मे जरूर हैं, लेकिन उन पूंजीपतियों पर कुछ निर्यंत्रण रखना चाहिए, अखबारो के लिए कुछ मार्ग-दर्शक सिद्धान्त तय करने चाहिए, उन पर कुछ नियन्त्रण लगाना चाहिए और वही नियन्त्रण इस आपातकालीन स्थिति मे लगाया गया है ।

एक ओर वे अखबार चल रहे है जिन्हे एकाधिकार वाले पत्र या मानोपली प्रेस कहा जाता है । दूसरी ओर वे छोटे छोटे अखबार हैं, जो स्वतन्त्र रूप से काम नही कर सकते है, जो दूसरों के रहमो-करम पर चल रहे है । इस लिए मेरा सुझाव है कि अखबारों का एक कार्पोरेशन बनाया जाना चाहिए और उसको सभी वर्गों के जाने-माने पत्रकारों, जर्नलिस्ट्स और कारेसपाडेंट्स आदि की सेवाये उपलब्ध कराई जानी चाहिए । वह कार्पोरेशन स्वतन्त्र रूप से काम करे, जिसमे पत्रकारिता को एक स्टैण्डर्ड स्थापित हो । सभी पार्टियों के लोग उस मे अपने विचार रख सके ।

यह कहा गया है कि इस आपातकालीन स्थिति से बहुत गडबडिया हुई हैं । मै समझता हू कि जब वे बडे बडे फासिस्ट नेता जेल भेज दिये गये जिन्होंने देश के लिए किसी जमाने मे बड़ी बड़ी कुर्बानियां की, लेकिन जिन्होंने बाद में महत्वाकाक्षा से प्रेरित होकर इस देश में बद-अमनी फैलाने की कोशिश की, जब उनके बारे में यह उचित समझा गया कि उनको बिना मुकदमा चलाये आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन बन्द रखा जाये, जब उनकी आवाज बन्द कर दी गई, तो जो अखबार उनकी ढफली पीटते थे, जो उनकी बातो का प्रचार करते थे, उनको आजादी कैसे दी जा सकती है ?

15.02 hrs.

[SHRI P PARTHASARATHY *in the Chair*]

यह तो एक नैसेसरी कारोलरी है कि अगर उन नेताओं को बन्द करना है, तो उनके चलाये हुए अखबारो पर प्रतिबन्ध लगाना भी जरूरी है, जो उन नेताओ के विचारो को छापते थे । मेरा खयाल है कि न तो गवर्नमेंट और न हम यह चाहते है कि आपातकालीन स्थिति हमेशा के लिए बनी रहे । लेकिन इसमे शिथिलता किस तरह से लाई जाये, इसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी आपोजीशन के लोगो पर है । उन लोगो ने समझा था कि यहा पर इतनी आजादी हो गई है कि जो चाहे कहो । इमर्जेंसी लागू होने से पहले इस सदन मे जोरो आवर के समय केवल इन बातो की चर्चा होती थी मारुति, इन्दिरा गाधी, ललित नारायण मिश्र, मोरारजी देसाई का अनशन, या फिर तुलमोहन राम कांड । इनने कानून पास किये गये, गवर्नमेंट ने इतना काम किया, इस तरफ कोई ध्यान नही दिया जाता था । विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यो ने यहा जो कुछ कहना होता था, उसको वे पहले से छपवा लेते थे । उन्होने स्पीच दी और वह फौरन अखबारो में छप गई । यह सारा वातावरण गन्दा करने की जिम्मेदारी उन लोगो की है ।

अब कहा जाता कि है रेडियो पर इन्दिरा गांधी का नाम और 20-सूत्री कार्यक्रम का जिक्र बहुत ज्यादा आता है। जब माननीय सदस्य भी यह कहते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है, तो फिर क्या जनता 20-सूत्री कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी से वंचित रखी जाये ? देश एक महान्

सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति में से गुजर रहा है । इसलिए प्रत्येक बच्चे बच्चे को यह एहसास होना चाहिए कि वह इस महान् क्रान्तिबेला में एक बड़ा भाग लेकर, एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है । अखबारों के जरिये गांव-गांव मे इसका प्रचार नही किया जा सकता है । इसलिए इका सब से सुलभ और प्रभावकारी साधन यह है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिये मे इसका प्रचार किया जाये ।

सवेरे से लेकर रात तक साहित्यिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक विषयो के कार्यक्रम रेडियो के द्वारा प्रसारित किये जाते है । जब इतने प्रोग्राम होते है, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है ? श्री राजदेव सिह ने कहा कि रेडियो से सिनेमा के अश्लील गाने प्रसारित किये जाते है । उनकी उम्र तो खैर ज्यादा हो गई है, कभी वह भी इन गानो को पसन्द करते होगे । कही ऐसा न समझा जाये कि मै बूढ़ा हू, और इस कारण मुझे टिकट न मिले, लिहाजा मैं अपने आप को जवानो के साथ रखना पसन्द करता हू और समझता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे गाने प्रसारित किये जाते है । श्री शुक्ल ने रेडियो के कार्यक्रमो में साहित्यिक अभिरुचि पैदा की है ।

"संसद् समीक्षा" के लिए बहुत कम समय दिया जाता है । इस लिए जो सदस्य पहले बोल लेते हैं, उनके भाषणो के बारे मे तो कुछ बता दिया जाता है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्तियों के सिर्फ नाम दिये जाते है ।लेकिन तब भी आकाशवाणी वाले यह कृपा करते हैं कि इतना वह कहते हैं कि इन्होंने भी शिरकत की । शुक्ला जी का जिस दिन आकाशवाणी पर प्रोग्राम होता है जो शुरू से सुनता है श्री *विद्याचरण शुक्ल का नाम उसको तो पता* रहता है नहीं तो इन के नाम का फायदा कभी कभी मुझे भी मिल जाता है । मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि आकाशवाणी मे जो संसद् समीक्षा आती है उसका टाइम आप बढा दें क्योंकि इससे सब प्रकार के संसद् सदस्यों को सन्तोष होगा । नही तो उनको यह रहता है कि यहा पर बोले, न अखबार मे उनका नाम छपा न रेडियो मे नाम आया । वैसे हम लोग कुछ बोले या न बोले, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता जो है वह समझती है कि इन्होंने कोई काम नही किया । तो हम लोगो के हित मे यह बात *आप अवश्य करे और उनका समय कुछ* बढ़ा दें । बाकी सब चीज आप की ठीक हैं । आपके मन्त्रालय की मागो का मैं समर्थन करता हूं । आपको बधाई देता हूं कि इतने थोड़े काल में अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व मे और कुशल प्रशासन से इसमे बड़े बड़े सुधार किए है और आप से बड़ी आशा है ।

SHRI ARJUN SETH (Bhadrak): It is a matter of satisfaction that the long-awaited national news agency has now come to serve the country. We have seen how the agencies controlled by big newspapers were starved of resources and could ill-afford *to engage in unnecessary duplication* of efforts. It is not new for some of the Opposition parties—whose Members have spoken earlier—to blame the Prime Minister and say that the Government headed by her has taken the country towards dictatorship. In fact, before the Emergency, these very Opposition parties were blaming the Government—and especially the Prime Minister—that she was supporting corrupt Ministers and people, and that as a result, the Government was spreading corruption in the

[Shri Arjun Seth].

country. After the Emergency, when the country is developing and the 20-point economic programme is being implemented, they have nothing to say except to blame the Government and say that it has thwarted democracy and that it is going towards dictatorship. Since they have no other means of spreading this very nasty politics amongst the people, they choose this forum to abuse the Government. Yesterday our Prime Minister, while speaking to some correspondents, had said that some of the Opposition parties have not changed their attitudes. They are still behaving in a manner which is injurious to the country. This very House is a witness to their way of thinking and of acting. So many Members have already replied to their allegations; and I must not take much time on it, since the time at my disposal is very short. As I said earlier, a national news agency with a network of organization, specially in the rural and urban areas, is very much desirable, more so now when the 20-point programme is being worked out. It is now all the more necessary for the news agency to focus its attention on the rural news and on the concerted efforts being made to improve the rural economy. It is the foremost duty of the news agency to distribute correct and unbiased news in the country without fear or favour, keeping in view the paramount interest of the nation.

We have seen that the Ministry has, specially after the emergency, done a lot of work to inform the people about the activities and performance of the Government. At the same time, I would draw the Minister's attention to o some of the facts which so many committees, specially the public Accounts Committee, have pointed out and also mentioned recently by the Comptroller and Auditor-General in his report for the year 1974-75, about the working of the Information Ministry, and would request him to take measures to set things right.

The accounts of the Children's Film Society for the period 1-4-72 to 31-3-75 were audited by the Auditor-General under section 14 of the Comptroller & Auditor-General (Duties, Powers and Conditions of Services) Act, 1971. The annual income and expenditure of the Society for three years were as follows:

(Rupees in Lakhs)

Year		Income	Expenditure
1972-73	..	5 20	13.95
1973-74	..	7.27	20 05
1974-75	..	7.81	24 98

So, the deficits for these years were Rs. 8.75 lakhs, Rs. 2.78 lakhs and Rs. 17;17 lakhs respectively. During this period Government gave grants-in-aid of Rs. 8.09 lakhs and Rs 8.50 lakhs and Rs. 16.76 lakhs.

In this regard, I would point out that the PAC in its 42nd Report (1965-66) recommended that "the Ministry should undertake a detailed evaluation of the working of the Society, both quantitatively and qualitatively." Further a Study Team of officials appointed in August 1967 to review the working of the Society, recommended specifically in 1968, along with the other recommendations, that the Government should give grant-in-aid of Rs. 25 lakhs in the first year, which may be reduced in the subsequent years by about Rs. 2 lakhs every year, and thus stabilised at Rs. 20 lakhs per year, and that Rs. 10 lakhs were to be raised by the Society. I fail to understand why Government has not yet accepted this recommendation, although the Committee has recommended a long way back during the sixties.

Similarly, we have seen that 46 countries, including India, participated in thte Fifth International Film Festival held in New Delhi. The test check in Audit disclosed Rs. 20,250/- were realised less and Government replied that steps were being taken

to recover the amount (Rs. 20,250) from the cinema owners who have not paid back the amount to the Government. So, I would like to know from the Government what action they have taken.

I am glad that *Yojana* is being published to educate the people especially in the rural areas, but I request the hon. Minister to see that it is published in all the languages, especially in Oriya. I am told it was going to be published in Oriya but has been held up for long, I do not know for what reason.

The Cuttack station of AIR has been functioning in a rental building since its inception. The building in which it is housed is very congested and not spacious enough for the purposes of the station. Therefore, I request the hon. Minister, especially since the ban on constructions has already been lifted, to see that the building for the station is taken up at the earliest

With these words, I support the Demands of the Ministry..

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam): प्रभु, दिव्य स्वतंत्रता के प्रकाश में मेरा देश जागृत हो, जहां हृदय में निर्भयता हो और मस्तक अन्याय के सामने नहीं झुकेगा।

I was told that even the above lines were censored some time back when a newspaper wanted to publish them. There have been other instances of censorship also. Mahatma Gandhi's picture walking in Noakhali published in a fortnightly was banned on the ground that as Gandhiji appears to be walking away, it might be considered that he was walking away from India in the emergency

I would like to quote a few sentences from Nehru's speech in 1936. He said:

> "A Government that has to rely on the Criminal Law (Amendment) Act and similar laws and suppress the press and literature, that bans hundreds of organisations, that keeps people in prison without trial and that does so many things that are happening in India today, is a Government that has ceased to have even a shadow of justification for its existence."

This is what her father said. He further said:

> "I can never adjust myself to these conditions. I find them intolerable, and yet I find many of my friends complacent about them, some even supporting them, and some, who have made the practice of sitting on the fence into a fine art, being neutral when such questions are discussed.". "Judging the British Government by its onslaught on civil liberations by its suppression of press freedom and its outlawing organisations and by its incarceration of people without trial, Nehru declared it as bereft of even a shadow of justification."

I do not know what Nehru would have said if he were living today about what is happening, about what the Members feel inside. They feel something inside, and they say something else, outside Against this hyprocrisy I think his sould would have cried out.

In one of the higher secondary textbooks I read a poem describing freedom, which says:

> "They are slaves who fear to speak
>
> For the fallen and the week They are slaves who will not choose
>
> Hatred suffering and abuse Rather than in silence shrink
>
> From the truth they need must think They are slaves who do not be
>
> In the right with two or three."

MR. CHAIRMAN: We are discussing Information and Broadcasting, we are not discussing the Home Ministry.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): She is not making a speech, she is quoting

SHRIMATI T. LAKSHMIKANT-HAMMA: I think I have every right to quote.

This lines show the difference between those who maintain their freedom of expression and those who do not because they do not have the courage.

This is what Mahatma Gandhi said about freedom of the press and about democracy:

> "Liberty of speech means that it is unassailed even when the speech hurts. Liberty of the Press can be said to be truly respected only when the press can comment in the severest terms upon and even misrepresent matters.... Freedom of press is a precious privilege that no country can forego."

In 1950, again, while addressing the All India Newspaper Editors Conference, Jawaharlal Nehru said:

> "I have no doubt that even if the Government dislikes the liberties taken by the press and considers them dangerous, it is wrong to interfere with the Freedom of the press I would rather have a completely free press with all the dangers involved in the wrong use of that freedom than a suppressed or regulated Press."

I know how much he disliked that freedom because of the concentration of the press in the hands of a few capitalists, but even then, he made that statement.

I hope that this also will not be censored if somebody wants to publish something about what Nehru said some time back. Suppression of the press has disadvantages, as it leads to rumours. How will the people get real information? Rumours spread like wildfire and wrong ones spread more quickly than correct ones. If some people say that some people have escaped from a certain jail, some may say that people have escaped from several jails and yet some others may say that lakhs of people have escaped. So, how will people get the correct information?

As you know, even what is spoken here is censored. Why do the Members speak here? They speak here so that people will understand that they are sort of projecting their feelings. But even that is suppressed and it is not allowed.

Here, again, I will quote what Gandhiji said about freedom:

> "Freedom of speech and pen is the foundation of Swaraj. If the foundation stone is in danger you must exert the whole of your might in order to defend that single stone. May God help you".

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA: We should not go back to the age of despotism or monarchy. I hope this country will not be allowed to go back to the age of Louis IX where so many examples of despotism are there. This should be avoided. Whether we say it or not, the image that we create in the minds of the people is more important that what we ourselves are trying to argue. What happened in Afghanistan and some other despotic countries? Freedom of the Press was suppressed, information was suppressed and books were banned. These things should not happen or it will create a misunderstanding that we are sort of moving towards despotic rule.

If somebody wants to project himself, I will never object because everyody—and even children—has a right to project his image. I would more particularly give this edvice to the young Youth Congress Leader. I will never criticise or attack him because I believe in taking the good side of everybody and not the bad side of him, whoever it may be. I believe in the essential good of human beings and their essential talent So let him

instead of trying to shine in somebody's borrowed colours, shine in his own right and glory and project himself.

If he believes in a certain ideology, let him come forward, let him fill the gap and provide the leadership; if the country lacks in alternatives, let him try. But it should not create jealously and heart-burning in the minds of the people that somebody is misusing the machinery; it creates a sort of disgust . . .

MR. CHAIRMAN : Please conclude. You have already taken ten minutes

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA: I want to say one thing about the beautiful work that the Song and Drama Division has done. There was a beautiful song-drama, Keno Upanishad, which they showed two years ago; it is a beautiful piece, it is a lesson for everybody to learn. It is difficult to bring it forth as a song-drama. More of these things should be encouraged.

For the International Women's year two publications were brought out, but they were not distributed even to women Members....

AN. HON. MEMBER: They should be distributed to men Members also.

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA: Let them first distribute those two books at least to women Members.

I must thank you, Mr. Chairman, for giving me this time.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput): I rise to support the Demands for Grants in respect of the Ministry of Information and Broadcasting.

First, I will take the press. I am a strong supporter of the freedom of press, the press which tells the truth and not the lies. Everybody wants freedom, but India does not want that, in the name of freedom, all sorts of things will be said which will divert the minds of the people and pollute the minds of the innocent people. Particularly, we, the younger generation, want to be far away from this type of untruth and false news. The press is to express the truth and not to suppress the truth.

My friend from the Opposition was asking whether the publicity which they want to give in the press will be published for the people. Of course, there is some restriction due to legislation and also due to the conditions in the country. The publicity which is needed in this country is more the economic publicity than the political publicity. Some people want publicity for achieving political gains. It should not be that the publicity should be confined only for political purposes, to demolish the image of the leaders by giving false statements. They only want to show themselves as statesmen by giving such statements. I am not a supporter of this type of thing.

Also, publicity is confined only to cities and it is not done in rural areas. We talk so much about publicity, but if you see the number of papers, there are nearly one thousand in Delhi; there are nearly 2,000 in Maharashtra, in all the states. They are publishing monthlies, dailies, weeklies, annuals and various magazines. But where are the media for carrying the news for the rural people? Government are encouraging, especially the Minister for Information and Broadcasting to propagate the programmes, plans and schemes to the innocent masses. But if the publicity is given only in these papers in cities how will the illiterate masses understand What are the media for giving publicity in rural areas?

MR. CHAIRMAN : Would you like to take some more time?

SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Then, you may continue on the next occasion. We have to take up the Private Members' business.

[Mr. Chairman].

We shall now take up Private Members' Business.

SHRI DHAMANKAR (Bhiwandi): Mr. Chairman, Sir, may I request you to give me a minute to bring to the notice of the House some fire incidents which have taken place in the suburban trains in Bombay. In this connection, I have met the Speaker also in the morning. I had given a notice for Calling Attention also.

MR. CHAIRMAN : There is nobody here to take note of it. You may raise it at some other time. Now the Private Members' Business has to be taken up.

SHRI DHAMANKAR: There have been fire incidents in a number of suburban trains.

MR. CHAIRMAN : Please cooperate, now the Private Members Business has to be taken up. You take up the matter with the Minister of Parliamentary Affairs. Now we take up Private Members Business.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
Sixty-second Report

15.31 hrs.

SHRI S. P. BHATTACHARYYA (Uluberia): I beg to move:

> "That this House do agree with the Sixty-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 14th April, 1976".

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That this House do agree with the Sixty-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 14th April, 1976."

The motion was adopted.

15.32 hrs.

RESOLUTION RE. MULTI-NATIONAL CORPORATIONS—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: Now we take up further discussion on the following Resolution moved by Shri H. N. Mukerjee:—

> "In view of the latest disclosures in several countries of the subversive and corrupting activities of the multinational corporations, this House urges upon Government to exercise the utmost vigilance against this menace which confronts all developing countries and to take concrete measures to bar the entry into the nation's economic life of foreign, and particularly US., multinationals."

The time allotted for this Resolution is two hours Shri Mukerjee has already taken two minutes, the time left is 1 hour and 58 minutes. He may continue his speech.

SHRI K. S. CHAVDA (Patna): Kindly increase the time, there are a number of speakers on this Resolution.

SHRI K. S. CHAVDA (Patna): The time may kindly be increased to four hours.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): Let us see, how the debate goes in. It is too premature, it has not even started.

MR. CHAIRMAN: Shri H. N. Mukerjee.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta—North-East): Mr. Chairman, Sir, I had read out my Resolution last time, which must have taken less than two minutes. It is self-explanatory and I consider it particularly important. That is why, I am sorry to have to preface my remarks with the observation that this Resolution which